JAGRAN Josh
www.jagranjosh.com

करेंट अफेयर्स

(मई 2020)

IAS | BANKING | SSC| NDA/CDS| AND OTHER COMPETITIVE EXAMS

लॉकडाउन 2.0

VISIT…

प्रस्तावना

आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को मद्देनजर रखते हुए, नवंबर माह की तमाम महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, वैश्विक तथा राज्यीय घटनाओं को इस संस्करण में संकलित करके, जागरणजोश आपके सामने **'करेंटअफ़ेयर्स मई 2020 ई-बुक'**प्रस्तुत कर रहा है.

'करेंट अफ़ेयर्स मई 2020 ई-बुक' (eBook) परीक्षाविशेषज्ञोंद्वारातैयारअद्यतनअध्ययनसामग्रीहै. इसमें विभिन्न विषयों' जैसे - राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, आर्थिक, कॉर्पोरेट, विज्ञान-तकनीक, खेल, पुरस्कार-सम्मान, पारिस्थितिकी-पर्यावरण, रिपोर्ट्स- सर्वेक्षण, पुस्तक-लेखक, आदिसंबधितपरीक्षाकेदृष्टिकोण सेउपयोगीघटनाओंपरआधाररतअद्वितीयकरेंटअफ़ेयर्सकासंकलनहै.

वर्तमान में आयोजित हो रही किसी भी प्रतियोगी तथा सरकारी नौकरी की परीक्षा के लिए करेंटअफ़ेयर्स एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषयवस्तु बन चुकी है. इसीलिए यह यह किसी भी तरह की परीक्षाओं में सफलता पाने या दिलाने में आपकी काफी मदद कर सकता है. इस दृष्टिकोण से करेंट अफेयर्स की महत्ता अपने आप बढ़ जाती है.

'करेंट अफ़ेयर्स मई 2020 ई-बुक' उन्हीं विचारों और रणनीती के साथ तैयार की गयी है जो आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओंजैसे- सिविल सेवा मुख्यपरीक्षा, एसएससी संयुक्तस्नातकस्तरीयपरीक्षाटीयर 1 एवंटीयर 2, एसएससी संयुक्तउच्चतरमाध्यभमक (10+2) स्तरीयपरीक्षा, एसबीआई पीओपरीक्षा, आईबीपीएसपीओपरीक्षा, संघ लोकसेवाआयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजितभारतीयआर्थिक/सांख्यिकी सेवापरीक्षा, भू-वैज्ञानीपरीक्षाआदिहेतुअत्यंतउपयोगीसाबित होगा.

Copyright ©Jagranjosh.com

All rights reserved. No part or the whole of this eBook may be copied, reproduced, stored in retrieval system or transmitted and/or cited anywhere in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise), without the written permission of the copyright owner. If any misconduct comes in knowledge or brought in notice, strict action will be taken.

Disclaimer: Readers are requested to verify/cross-check up to their satisfaction themselves about the advertisements, advertorials, and external contents. If any mishappening, ill result, mass depletion or any similar incident occurs due to any information cited or referenced in this e-book, Editor, Director/s, employees of Jagranjosh.com can't be held liable/responsible in any matter whatsoever. No responsibilities lie as well in case of the advertisements, advertorials, and external contents.

इंडेक्स

राष्ट्रीय | भारत 7
अंतरराष्ट्रीय | विश्व 19
विज्ञान | तकनीक 31
राज्य 43
न्यूज़ कैप्सूल 49
कार्पोरेट 52
अर्थव्यवस्था 56
पर्यावरण 99

JAGRAN Josh

Mathematics Formula & Shortcuts eBook

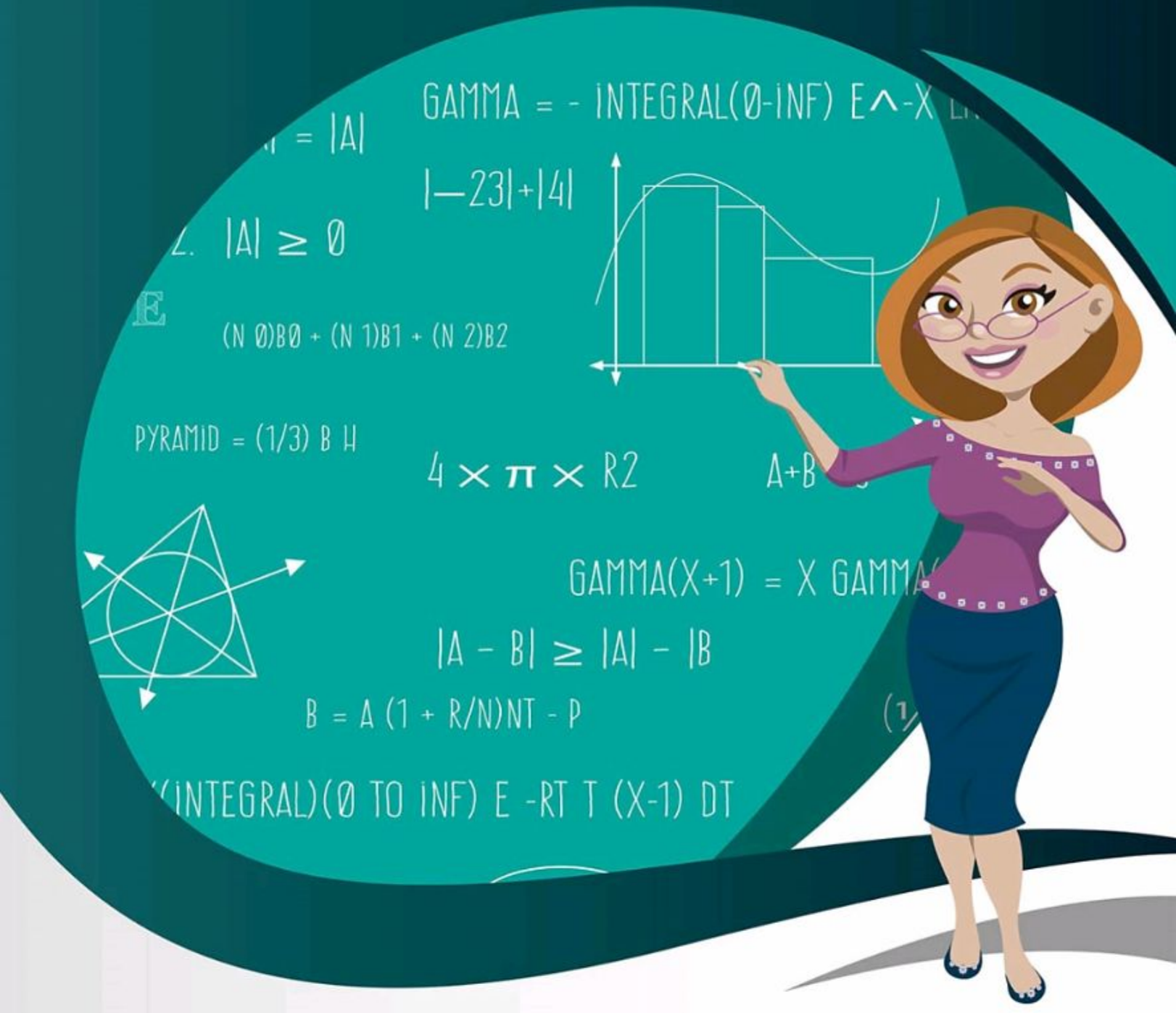

for All Competitive Exam Like

IAS | BANKING | SSC | NDA/CDS

To download visit : https://goo.gl/EOX9f9

राष्ट्रीय | भारत

'Aarogya Setu' मोबाइल ऐप क्या है, कोरोना वायरस पर ऐसे करेगा काम

कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु घरों में जिन लोगों को क्वारंटीन किया गया है उन पर अब सरकार नज़र रखने के लिए तकनीक का सहारा ले रही है. इसके साथ ही तकनीक के ज़रिए ही कोरोना संक्रमित लोगों के मूवमेंट पर भी नज़र रखी जा रही है. केंद्र सरकार ने हाल ही में 'आरोग्य सेतु' ऐप लॉन्च किया है. इस ऐप के ज़रिए लोग अपने आसपास कोरोना के मरीज़ों के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं.

केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस (Corona virus) से निपटने के लिए भारत सरकार हरसंभव कदम उठा रही है. सरकार ने COVID-19 को ट्रैक करने के लिए आरोग्य सेतु (Aarogya Setu) नाम का एक ऐप लॉन्च किया है. सरकार इस एप के जरिए संक्रमित लोगों की लोकेशन को ट्रैक कर सकेगी.

सरकार का मुख्य उद्देश्य इस ऐप के जरिए यूजर्स की मदद करना है ताकि वे यह जान सकें कि क्या वे कोरोना से संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए हैं या नहीं. यूजर्स के स्मार्टफोन के लोकेशन डाटा और ब्लूटूथ के इस्तेमाल से संक्रमण का पता लगाया जाएगा.

सरकार इससे पहले भी 'कोरोना कवच' नाम के मोबाइल एप को पेश कर चुकी है. कोरोना ट्रैकर ऐप आरोग्य सेतु फिलहाल 11 भाषाओं में काम करेगा जिसमें हिंदी और अंग्रेजी भी शामिल हैं. इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप यूजर को खुद को महामारी से बचाने के टिप्स भी देती है.

कैसे काम करती है ऐप?

यह ऐप फोन के लोकेशन डाटा और ब्लूटूथ का उपयोग कर देखती है कि कहीं यूजर किसी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं आया है. इसे संक्रमितों का डाटाबेस के साथ

जोड़ा गया है. यह ऐप लोकेशन डाटा के जरिये यूजर्स की लोकेशन की पता लगाती है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की सहायता से यह देखा जाता है कि यूजर किसी संक्रमित व्यक्ति के छह फीट के दायरे में आया है या नहीं.

यह यूजर को इसके आधार पर अगला कदम उठाने की सलाह देती है. यदि यूजर 'हाई रिस्क' एरिया में हैं तो ऐप उसको कोरोना वायरस टेस्ट कराने, हेल्पलाइन पर फोन करने और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाने के लिए सलाह देती है.

कई फीचर्स से है लैस

आरोग्य सेतु ऐप में कई और फीचर भी दिए गए हैं. इसमें दिए गए चैटबॉच की सहायता से आप कोरोना वायरस के लक्षण को पहचान सकते हैं. यह ऐप हेल्थ मिनिस्ट्री के अपडेटस और भारत के हर राज्यों के कोरोना वायरस हेल्प लाइन नंबर की सूची भी देता है.

इसके अतिरिक्त आरोग्य सेतु ऐप यूजर को खुद को महामारी से बचाने के टिप्स भी देती है. यदि कोई यूजर कोरोना वायरस से संक्रमित पाया जाता है तो यह उसका डाटा सरकार को भेज देती है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस पर वीडियो संदेश जारी किया, लोगों को दिया यह सलाह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 03 अप्रैल 2020 को एक वीडियो संदेश साझा करके राष्ट्र के नाम संदेश जारी किया. उन्होंने कोरोना संकट काल के दौरान अपने तीसरे संदेश मे कहा है कि कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान देश के लॉकडाउन को 9 दिन पूरे हो गए हैं. इस चुनौतीपूर्ण समय में ये भाव प्रकट हुआ है कि देश एक होकर इस महामारी का सामना कर सकता है.

कोरोना वायरस महामारी के बीच देश में चल रहे लॉकडाउन पर प्रधानमंत्री मोदी लगाता नजर बनाए हुए हैं. कोरोना वायरस से लड़ रहे देश के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो संदेश दिया. प्रधानमंत्री ने 09 अप्रैल को सुबह 9 बजे लोगों के साथ एक वीडियो संदेश साझा किया था.

प्रशासन ने इसको लेकर पूरी एकाग्रता के साथ कार्य किया

प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन का देश की जनता ने पालन करने की पूरी कोशिश की है और शासन, प्रशासन ने इसको लेकर पूरी एकाग्रता के साथ कार्य कर रहा है. इस मुश्किल समय में लोगों ने अनुशासन दिखाया है और विश्व के कई देश भारत से सीख रहे हैं.

प्रधानमंत्री ने यह की थी अपील

प्रधानमंत्री के अपील पर लोग 5 अप्रैल 2020 को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दीया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं थे.

प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में क्या कहा था?

प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि हम सबको मिलकर कोरोना संकट के अंधकार को चुनौती देनी है. इस महामारी को प्रकाश की ताकत का परिचय कराना है. उन्होंने कहा था कि इस दौरान घर की सभी लाइटें बंद करके, घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दीया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं.

दरअसल, 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू के दौरान शाम पांच ताली, थाली, घंटी आदि बजाकर कोरोनावीरों का धन्यवाद किए जाने की अपील पर कई लोग घरों से बाहर निकल गए थे.

कोरोना संकट के दौरान तीसरा संदेश

प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले 19 मार्च को और 24 मार्च को रात 8 बजे देश को संबोधित किया था. 24 मार्च को उन्होंने देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाए जाने के बारे में बताया था और 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान पूरे 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी.

कोविड-19 से जुड़ी शिकायतों के लिए राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड का शुभारंभ

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 01 अप्रैल 2020 को कोविड - 19 शिकायतों के लिए राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड शुरु किया. इस डैशबोर्ड को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा निर्मित और संचालित किया जा रहा है.

DARPG की तकनीकी टीम द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कोविड -19 से संबंधित विभिन्न जन शिकायतों का निवारण किया जाएगा. यह टीम सभी विभागों और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों/ मंत्रालयों के साथ केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) में शिकायतें प्राप्त करेगी.

लोक शिकायत और सुझाव से संबंधित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित DARPG द्वारा अधिकार प्राप्त समूह अधिकारियों की सिफारिश के आधार पर कोविड -19 से संबंधित शिकायतों के लिए राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड की स्थापना की गई है.

उद्देश्य: राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड कोविड - 19 प्रतिक्रिया गतिविधियों का त्वरित और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा.

राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड की प्रमुख विशेषताएं:

- राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड शुरु होने के पहले ही दिन डॉ. जितेंद्र सिंह ने व्यक्तिगत रूप से कोविड-19 संबंधित केंद्र सरकार की 262 शिकायतों की स्थिति और राज्य सरकारों की 83 शिकायतों की समीक्षा की.
- राष्ट्रीय निगरानी बोर्ड को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से 43 शिकायतें, वित्त मंत्रालय से 26 शिकायतें और विदेश मंत्रालय से 31 शिकायतें मिलीं.
- सरकार के वरिष्ठ अधिकारीयों के द्वारा दैनिक आधार पर इस शिकायत पोर्टल की निगरानी करने के साथ ही इसे अद्यतन किया जायेगा.

राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड निम्नलिखित शिकायतों का निवारण करता है:

- आवश्यक आपूर्ति के संबंध में शिकायतें
- लॉकडाउन के उल्लंघन से जुड़ी शिकायतें
- परीक्षा से संबंधित शिकायतें
- क्वारंटाइन सुविधाएं
- विदेशों से निकासी के लिए अनुरोध
- ऋणों पर ब्याज पुनर्भुगतान का पुनर्निर्धारण

राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड का महत्व:

राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड का संचालन शुरू होने के दो दिन के भीतर ही नागरिकों की लगभग 62 शिकायतों का समाधान किया गया है.

कोविड-19 पर जल्द चर्चा करेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य: UN महासचिव

संयुक्त राष्ट्र के महाचसिव एंटोनियो गुटेरेस ने दुनिया पर मंडरा रहे कोरोना वायरस (कोविड-19) के खतरे के बीच कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के सदस्य देश महामारी पर चर्चा के लिए जल्द ही बैठक करेंगे. कोरोना वायरस की वजह से विश्वभर में 10 लाख 20 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 70 हजार के करीब लोगों की मौत हो चुकी है.

संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक ब्रीफिंग के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के महाचसिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि मुझे सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष से परिषद के सदस्य देशों को संबोधित करने का निमंत्रण मिला है, जो मैं अगले हफ्ते करूंगा. कोरोना वायरस के वैश्विक प्रकोप के बाद से 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद ने एक बार भी बैठक नहीं की है.

यह पद पहले चीन के पास था

डोमिनिकन रिपब्लिक ने चीन के बाद एक अप्रैल से यूएनएससी की अध्यक्षता संभाली है. इससे पहले 31 मार्च तक यह पद चीन के पास था.

संयुक्त राष्ट्र के महाचसिव गुटेरेस ने कहा कि अफगानिस्तान में जहां लड़ाई बढ़ गई है. वहां समय आ गया है कि सरकार और तालिबान मिलकर काम करें और लड़ाई छोड़ दें क्योंकि कोरोना वायरस लोगों को प्रभावित कर रहा है.

संयुक्त राष्ट्र के महाचसिव ने कहा कि मेरा उद्देश्य अब युद्ध को रोकना है, निर्णय करना नहीं है. उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य अब यह सुनिश्चित करना है कि युद्ध विराम, जिसके तकनीकी पहलुओं पर दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों द्वारा सहमति व्यक्त की गई.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के छः प्रमुख अंगों में से एक अंग है. इसका उत्तरदायित्व है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अनिवार्य निर्णयों को घोषित करने का अधिकार भी है.

ऐसे किसी निर्णय को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव कहा जाता है. इसे विश्व का सिपाही भी कहते है क्योंकि वैश्विक शांति और सुरक्षा की जिममेदारी इसी के पास में है.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य है. इसमें से पांच स्थाई सदस्य और दस अल्पकालिक सदस्य है. पांच स्थाई सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका है.

इन पांच देशो को कार्यविधि मामलों में तो नहीं पर विधिवत मामलों में प्रतिनिषेध शक्ति है. बाकी के दस सदस्य क्षेत्रीय आधार के अनुसार दो साल की अवधि के लिए सामान्य सभा द्वारा चुने जाते है.

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकारी और प्राइवेट लैब में मुफ्त हो कोरोना की जांच

सुप्रीम कोर्ट ने 08 अप्रैल 2020 को देश में कोरोना वायरस महामारी के बीच बड़ा फैसला सुनाया था. कोर्ट ने आदेश दिया कि मान्यता प्राप्त सरकारी या प्राइवेट लैब में कोरोना वायरस की जांच मुफ्त में होगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के लिए भारत सरकार को निर्देश जारी किए हैं.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार तुरंत इस संबंध में आवश्यक दिशा -निर्देश जारी करेगी. सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार निजी लैब में भी कोरोना का टेस्ट फ्री होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस की जांच से जुड़ी एक याचिका पर अंतरिम आदेश देते हुए केंद्र सरकार से 2 हफ्ते में हलफनामा दायर करने को कहा था.

मुख्य बिंदु

- सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार निजी लैब में भी कोरोना का टेस्ट फ्री होगा. यह टेस्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन या आईसीएमआर से मंजूरी वाली लैब में या फिर एनएबीएल से मान्यता प्राप्त लैब में ही होगा. इस मामले में दो हफ्ते बाद फिर सुनवाई होगी.
- सुप्रीम कोर्ट ने वकील शशांक देव सुधी की याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया. इससे पहले इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की जांच को लेकर निजी लैब द्वारा लिए जा रहे 4,500 रुपये को लेकर कहा है कि ये अपनी मनमानी से पैसे नहीं वसूल सकते.
- कोर्ट ने कहा निजी लैब को कोरोना जांच के लिए पैसे लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिए. हम इस मामले पर आदेश पारित करेंगे.
- सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा हम निजी लैब को कोविड-19 के परीक्षण के लिए पैसे वसूलने की अनुमति नहीं देते हैं. सरकार को इसकी जांच मुफ्त में करनी चाहिए.

- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल जनरल तुषार मेहता को सुझाव देते हुए कहा कि निजी लैब को जांच हेतु ज्यादा शुल्क न दें. कोई ऐसा तंत्र विकसित करें जिसके तहत निजी लैब के टेस्ट राशि को सरकार वापस कर सके.
- सॉलिसिटर जनरल जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 118 प्रयोगशालाओं में रोजाना 15 हजार टेस्ट हो रहे थे. इन 47 निजी प्रयोगशालाओं को जोड़ा गया.
- सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि यह राज्य और पुलिस प्रशासन का दायित्व है कि उन सभी जगहों पर आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराए जहां कोरोना के संक्रमित मरीज पाए गए हैं या जहां लोगों को क्वारंटीन किया गया है और जहां लोगों की जांच के लिए मेडिकल स्टाफ को जाना होता है.

पृष्ठभूमि

कोर्ट ने कहा कि दुनिया भर के देशों में कोरोना वायरस से जो लोग पीड़ित हैं उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट में 31 मार्च को एक याचिका दायर की गई थी जिसमें सरकारी और निजी लैब में कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच निशुल्क कराने का दिशानिर्देश क्रेंद्र सरकार को देने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने इसी याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था.

जस्टिस नागेश्वर राव और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को ईमेल आदि के माध्यम से याचिका की प्रति सॉलिसिटर जनरल को देने के निर्देश दिए थे.

प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी घोषणा: भारत में 3 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन, और सख्त होंगे नियम

कोरोना संकट और लॉकडाउन के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2020 को देश को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि देश में 3 मई तक लॉकडाउन जारी किया जाएगा. अगले एक सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी. 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को परखा जाएगा. जो क्षेत्र इस अग्निपरीक्षा में सफल होंगे, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है.

कोरोनावायरस पर यह उनका 26 दिन में देश के नाम चौथा संदेश है. कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू 21 दिन के लॉकडाउन की अवधि 14 अप्रैल 2020 को खत्म होने जा रही है. वहीं, राज्यों के मुख्यमंत्रियों व अधिकारियों ने भी प्रधानमंत्री को लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया है. प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 24 मार्च को 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी.

देश के नाम चौथा संदेश

प्रधानमंत्री मोदी का कोरोना वायरस पर यह उनका 26 दिन में देश के नाम चौथा संदेश है. प्रधानमंत्री ने 19 मार्च को देश को संबोधित किया था और जनता कर्फ्यू (22 मार्च 2020) लगाने की बात कही थी. 22 मार्च को देशभर में सबकुछ बंद रहा.

मोदी ने 24 मार्च को दूसरी बार देश संबोधित किया और कोरोना संक्रमण रोकने के लिए 25 मार्च से 14 अप्रैल तक देशव्यापी लॉकडाउन का घोषणा किया था. प्रधानमंत्री मोदी ने 3 अप्रैल को एक वीडियो संदेश जारी किया. इस दौरान लोगों से 5 अप्रैल की रात 9 बजे 9 मिनट के लिए घरों की लाइट बंद कर घरों में दीये, मोमबत्ती और मोबाइल की लाइट जलाकर एकजुटता दिखाने की अपील की थी.

प्रधानमंत्री ने कहा- जान भी और जहान भी, दोनों बचाना जरूरी

प्रधानमंत्री ने हाल ही में देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की थी. प्रधानमंत्री ने बैठक में मुख्यमंत्रियों से कहा कि "जान है तो जहान है.

जब मैंने राष्ट्र के नाम संदेश दिया था, तो शुरुआत में इस पर जोर दिया था कि हर नागरिक की जान बचाने के लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत जरूरी है.

देश के ज्यादातर लोगों ने बात को समझा और घरों में रहकर दायित्व निभाया. अब भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, समृद्ध और स्वस्थ भारत के लिए जान भी, जहान भी, दोनों पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है.

आरोग्य सेतु ऐप 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बना

नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (सीईओ) अमिताभ कांत ने 15 अप्रैल 2020 को कहा कि सरकार के आरोग्य सेतु ऐप के यूजर्स की संख्या केवल 13 दिनों में 5 करोड़ पहुंच गई है. इस लिहाज से यह दुनिया का तेजी से लोकप्रिय होने वाला ऐप बन गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को राष्ट्र के नाम संबोधन में लोगों से इस ऐप को डाउनलोड करने की अपील की थी. आरोग्य सेतु ऐप को कोरोना वायरस मरीजों को ट्रैक करने के लिए विकसित किया गया है. भारतीय सेना ने भी जवानों को दी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी है. वहीं प्रसार भारती ने अपने कर्मचारियों के लिए ऐप इंस्टाल करना अनिवार्य कर दिया है.

नीति आयोग के सीईओ ने 15 अप्रैल 2020 को ट्वीट किया कि टेलीफोन को पांच करोड़ लोगों तक पहुंचने में 75 साल लगे, रेडियो को 38 साल, टेलीविजन को 13 साल, इंटरनेट को चार साल, फेसबुक को 19 महीने और पोकेमॉन गो को 19 दिन लगा. लेकिन, कोरोना से लड़ाई के लिए लांच किए गए देश के पहले आरोग्य सेतु एप को पांच करोड़ लोगों तक पहुंचने में सिर्फ 13 दिन लगे जो एक विश्व रिकॉर्ड है.

कोरोना वायरस को ट्रैक करने वाले इस ऐप ने 5 करोड़ डाउनलोड के साथ ही दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले मोबाइल ऐप का भी खिताब हासिल कर दिया. एंड्राइड पर 99 प्रतिशत डाउनडोल के साथ ही इसने गेमिंग ऐप Pokemon GO को भी पछाड़ दिया. Pokemon GO ने साल 2016 में 19 दिनों में 50 मिलियन ऐप डाउनलोड का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन अब इस आरोग्य सेतु ऐप ने उसे पछाड़ दिया है.

क्या है आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप

आरोग्य सेतु एप को कोरोना वायरस के संक्रमित को रोकने के मकसद से तैयार किया गया है. आरोग्य सेतु ऐप लोगों को बताएगा कि आप किसी कोरोना संक्रमित शख्स के संपर्क में आए हैं या नहीं.

इसके अलावा इस ऐप से आप यह भी पता लगा सकते हैं कि आपको कोरोना संक्रमण का कितना खतरा है.

केंद्र सरकार ने किसानों के लिए लॉन्च किया Kisan Rath Mobile App, जानें विस्तार से

केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 17 अप्रैल 2020 को किसान-रथ (Kisan Rath) नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया. कोरोना वायरस (कोविड-19) के कारण देश में तीन मई तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है. इस लॉकडाउन में किसानों को फसल और सब्जी बेचने में काफी परेशानी हो रही है. केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों की इस परेशानी को देखते हुए यह ऐप लॉन्च किये है.

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण (Corona Virus) से पैदा हुए संकट की घड़ी में यह मोबाइल ऐप कृषि उत्पादों के सुचारु परिवहन में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इसके लांच होने के पहले ही दिन पांच लाख से अधिक वाहन उपलब्ध हो गए हैं. केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि हमने कंट्रोल रुम भी बनाया है और सभी राज्यों से भी किसानों के हित में ऐसे कदम उठाने को कहा है.

उद्देश्य

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि उत्पादों के परिवहन में सुगमता लाने के उद्देश्य से किसान रथ मोबाइल ऐप लांच किया है. किसान रथ ऐप के जरिए किसान और व्यापारी आसानी से फसलों की खरीद और बिक्री कर सकते हैं.

ऐप डाउनलोड कैसे करें?

किसान रथ ऐप को गूगल प्ले-स्टोर से डाउनलोड करें. ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर जैसी जानकारियों के साथ पीएम किसान के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा. व्यापारी को कंपनी का नाम, अपना नाम और मोबाइल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा.

रजिस्ट्रेशन करने के बाद मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड के जरिए ऐप में लॉगिन किया जा सकता है. किसान रथ अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु भाषा में उपलब्ध है.

किसान रथ ऐप का फायदा

केंद्र सरकार ने किसान रथ को लॉकडाउन की स्थिति में सब्जियों और फसलों की खरीद-बिक्री के लिए लॉन्च किया है, ताकि किसान आसानी से अपने सामान को बेच सकें और व्यापारी खरीद सकें. यह ऐप देशभर के किसानों को और व्यापारियों को कृषि उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने में मदद करेगा. इस ऐप से किसानों और व्यापारियों को परिवहन वाहनों के बारे में जानकारी मिलेगी. ऐप में ट्रक के आने का समय और स्थान के बारे में भी जानकारी होगी. इसके बाद किसान एक तय समय और स्थान पर जाकर फल, सब्जियों और अनाज को बेच सकेंगे. इस ऐप के जरिए ट्रांसपोर्टस भी सामान की ढुलाई के लिए अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.

कृषि मंत्रालय ने क्या कहा?

कृषि मंत्रालय ने कहा कि पांच ऑन-लाइन ट्रक बुकिंग कंपनियों ने 5.7 लाख से अधिक ट्रकों को ऐप पर सूचीबद्ध किया है. नई प्रणाली से किसानों, ट्रांसपोर्टरों और एग्रीगेटर्स और सरकार सबके लिए लाभ होने की उम्मीद है. यह मोबाइल ऐप देश के सभी राज्यों के किसानों के लिए जारी किया गया है.

--X----------X----------X--

अंतरराष्ट्रीय | विश्व

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग CAA के खिलाफ पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, भारत ने कहा- यह हमारा आंतरिक मामला

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) ने हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ भारत के सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के उच्चायुक्त ने भारत को दी है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीएए भारत का आंतरिक मामला है तथा यह कानून बनाने वाली भारतीय संसद के संप्रभुता के अधिकार से संबंधित है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि जिनेवा में हमारे स्थायी दूतावास को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बैश्लेट ने सूचित किया कि उनके कार्यालय ने सीएए 2019 के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है.

यूएनएचआरसी के इस कदम पर भारत की ओर से सख्त आपत्ति जताई गई है. इस मामले पर विदेश मंत्रालय का कहना है कि 'यह भारत का पूरी तरह से आंतरिक मामला है. किसी विदेशी पक्ष को भारत की संप्रभुता से जुड़े विषयों पर अदालत में जाने का अधिकार नहीं है.

यूएनएचआरसी ने अपने आवेदन में क्या कहा?

यूएनएचआरसी ने अपने आवेदन में कहा है कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था 'सीएए' की आलोचना करती है. यूएनएचआरसी के अनुसार, सीएए मुस्लिम प्रवासियों को जोखिम में डालता है. इसमें यह भी कहा गया है कि, सीएए के औचित्य और निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं. यूएनएचआरसी द्वारा दाखिल 12 पन्ने के आवेदन में कहा गया है कि सीएए भारत के व्यापक मानवाधिकार दायित्वों तथा अंतरराष्ट्रीय के वचनों के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल उठाता है.

भारत सरकार ने अपने बयान में क्या कहा?

भारत सरकार ने अपने बयान में कहा कि नागरिकता संशोधन एक्ट (सीएए) भारत के संविधान की सभी मूल्यांकन को पूरा करता है. मानवाधिकार को लेकर देश के द्वारा किए गए सालों पहले किए गए बंटवारे के दौरान के वादे को पूरा करता है.

विदेश मंत्रालय ने साफ-साफ कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो कानून के आधार पर चलता है. भारत में कानूनी व्यवस्था पर पूरा विश्वास है और हमें आशा है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा पक्ष स्पष्ट हो जाएगा.

भारत में भी नागरिकता संशोधन अधिनियम के मसले पर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में हैं. सुप्रीम कोर्ट अभी इस मसले पर सुनवाई कर रही है. हालांकि, विदेश मंत्रालय अपने प्रत्येक बयान में कह चुका है कि ये भारत का आंतरिक मामला है तथा कोई बाहरी देश इस मामले में दखल ना दे.

नागरिकता संशोधन एक्ट 2019 क्या है?

यह एक्ट नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करता है. इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी ऐसा व्यक्ति भारतीय नागरिकता हासिल कर सकता है जो भारत में जन्मा हो या जिसके माता/पिता भारतीय हों या फिर वे एक तय समय के लिए भारत में रहा हो.

अधिनियम में नागरिकता देने के और भी प्रावधान हैं. यह अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने से रोकता है. नागरिकता संशोधन बिल 2019, तीन देशों (पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान) से आए 6 समुदायों के लोगों को इस प्रावधान में ढील देने की बात करता है.

नागरिकता संशोधन बिल को लोकसभा ने 10 दिसम्बर 2019 को तथा राज्यसभा ने 11 दिसम्बर 2019 को परित कर दिया था. भारत के राष्ट्रपति ने 12 दिसम्बर को इसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी और यह विधेयक एक अधिनियम बन गया.

फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट में भारत को 83वां स्थान प्राप्त हुआ

एक अमेरिकी संस्था 'फ्रीडम हाउस' द्वारा हाल ही में 'फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020' नामक एक रिपोर्ट जारी की गई. रिपोर्ट के तहत 195 देशों में वर्ष 2019 के दौरान स्वतंत्रता की स्थिति का मूल्यांकन किया गया है. इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति अच्छी नहीं बताई गई है.

रिपोर्ट तैयार करने के लिए दो संकेतकों का प्रयोग किया गया है जिनमें राजनीतिक अधिकार (0–40 अंक) और नागरिक स्वतंत्रता (0–60 अंक) शामिल किये गये हैं. इस रिपोर्ट में फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन को 100 में से 100 अंक मिले हैं जबकि भारत को 83वां स्थान दिया गया है.

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2019 में भारत की हिंदू राष्ट्रवादी सरकार द्वारा कश्मीर में लागू किये गये विभिन्न निर्णयों से महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है.

फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट में भारत

- इस रिपोर्ट में भारत में सरकार द्वारा कश्मीर में लगाये गये विभिन्न प्रतिबंधों का हवाला दिया गया है.
- इस रिपोर्ट में भारत को तिमोर-लेस्ते और सेनेगल के साथ 83वें स्थान पर रखा गया है.
- 'स्वतंत्र' वर्ग के रूप में वर्गीकृत देशों में केवल ट्यूनीशिया को भारत से कम स्कोर प्राप्त हुआ है।
- भारत का स्थान इस वर्ष विश्व के 25 सबसे बड़े लोकतंत्रों के स्कोर में सबसे कम है. इस वर्ष भारत का स्कोर चार अंक गिरकर 71 हो गया है.

- भारत ने राजनीतिक अधिकार श्रेणी में 40 में से 34 अंक प्राप्त किये हैं, लेकिन नागरिक स्वतंत्रता श्रेणी में इसे 60 में से केवल 37 अंक प्राप्त हुए हैं.
- इस रिपोर्ट के पिछले संस्करण में भारत को 75 अंक प्राप्त हुए थे.

भारत की कमज़ोर स्थिति के कारण

- फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा कश्मीर में शटडाउन किया गया है. साथ ही साथ नागरिक रजिस्टर और नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के अलावा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के चलते भारत की स्थिति कमज़ोर हुई है.
- भारत में हो रहे विरोध प्रदर्शनों और सरकार के रुख के कारण भारत के धर्मनिरपेक्ष और समावेशी स्वरुप पर खतरा उत्पन्न हो गया है
- इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान सरकार ने देश की बहुलता और व्यक्तिगत अधिकारों के लिये अपनी प्रतिबद्धता से खुद को दूर कर लिया है, जिसके बिना लोकतंत्र लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है.
- रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को लंबे समय से चीन के लोकतांत्रिक प्रतिरोधी के रूप में देखा जाता रहा है और इसलिये इस क्षेत्र में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है. अब यह दृष्टिकोण बदल रहा है और चीन के समान भारत को भी लोकतांत्रिक मुद्दों पर आलोचना झेलनी पड़ रही है.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अमेरिका-तालिबान शाति समझौते का किया समर्थन

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में शांति लाने और अमेरिकी सेना की वापसी हेतु अमेरिका और तालिबान के बीच हाल ही में हुए समझौते का स्वागत करने वाले एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है. यह समझौता अफगानिस्तान में शांति का मार्ग प्रशस्त करने हेतु है.

अमेरिका और तालिबान के बीच 29 फरवरी को दोहा में समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे. यूएनएससी के सभी 15 सदस्यों ने अमेरिका द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का 10 मार्च 2020 को समर्थन किया. इस प्रस्ताव में अमेरिका एवं तालिबान के बीच शांति और समझौते की संयुक्त घोषणा का समर्थन किया गया है.

इस प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र परिषद ने अफगानिस्तान सरकार से महिलाओं सहित राजनीतिक और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ गहन बातचीत के जरिये शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निवेदन किया है. संयुक्त राष्ट्र , अफगानिस्तान में लम्बे समय से जारी संघर्ष समाप्त करने को तत्पर है .

तालिबान ने क्या कहा?

तालिबान ने हाल ही में कहा था कि वे अब भी अफगानिस्तान के 'वैध शासक' हैं और यह उनका कर्तव्य है कि वे साल 2001 में अमेरिकी फौज द्वारा बेदखल किए जाने से पहले की 'इस्लामी सरकार' को फिर से बहाल करें. तालिबान ने कहा था कि अमेरिका से दोहा में हुए शांति समझौते से इस स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ा है.

तालिबान के साथ शांति समझौते के अनुसार अमेरिका धीरे-धीरे अपने सारे सैनिक वापस बुलाएगा. अफगानिस्तान के सरकार के अनुसार शांति का मौहल बनाए रखने के लिए 1500 तालिबानी कैदी रिहा किए जाएंगे.

अमेरिका-तालिबान शांति समझौता क्या है?

यह समझौता अफगानिस्तान में शांति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए है. अमेरिका समझौते के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद अपने सैनिकों की संख्या में धीरे-धीरे कमी लाएगा. तालिबान ने इस समझौते के अंतर्गत बदले में अमेरिका को भरोसा दिलाया है कि वे अल-कायदा और दूसरे विदेशी आतंकवादी समूहों से अपना नाता तोड़ लेगा. दोनों पक्षों ने लगभग 18 महीने की वार्ता के बाद इस शांति समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कहा कि समझौते के कार्यान्वयन के दौरान अफगानिस्तान में तैनात विदेशी सेनाओं को व्यवस्थित रुप से और जिम्मेदार तरीके से हटना चाहिए. अफगानिस्तान की स्थिति का स्थिर संक्रमण बनाए रखने तथा सुरक्षा वैक्यूम से बचने की जरूरत है.

अमेरिकी सरकार का बड़ा फैसला, ईरान पर बढ़ाएगा परमाणु प्रतिबंध

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30 मार्च 2020 को ईरान पर अतिरिक्त 60 दिनों के लिए 4 परमाणु प्रतिबंधों का नवीनीकरण करने का फैसला किया है. अमेरिका ईरान पर अपने प्रतिबंधों को और आगे बढ़ा रहा है. अमेरिकी विदेशी मंत्रालय के अनुसार, ईरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति कभी नहीं दी जाएगी

प्रतिबंधों का मुख्य उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है. इसके साथ ही तेहरान के लिए न्यूक्लियर हथियार बनाना मुश्किल होगा.

अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के विकास की बारीकी से निगरानी करेंगे और इन प्रतिबंधों को किसी भी समय समायोजित कर सकते हैं.

अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा?

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति कभी नहीं दी जाएगी. राष्ट्रपति ट्रंप ने साल की शुरुआत में कहा था कि ईरान का परमाणु हथियार रखना स्वीकार नहीं कर सकते, यह विश्व के शांति और सुरक्षा का सवाल है.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने क्या कहा?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने कोरोना वायरस का सामना कर रहे ईरान जैसै देशों पर लगाए गए प्रतिबंधों का तत्काल पुनः मूल्यांकन का आग्रह किया, ताकि चिकित्सा तंत्र को नुकसान पहुंचने से बचाया जा सके. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने एक बयान में कहा कि इस अहम समय में, वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य कारणों और इन देशों के लाखों लोगों के अधिकार एवं जिंदगियों के समर्थन में इन प्रतिबंधों में ढील देनी चाहिए या निलंबित कर देना चाहिए.

पृष्ठभूमि

अमेरिका ने साल 2018 में ईरान न्यूक्लियर डील रद्द करके प्रतिबंध लगा दिए थे .अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से तनाव का माहौल है. अमेरिका ने बीते दिनों एक मिसाइल हमले में ईरान के बड़े कमांडर को मार गिराया था, जिसके बाद दोनों ओर से हथियारों का इस्तेमाल हुआ. अमेरिका ने तभी ईरान पर कुछ बड़े प्रतिबंध लगा दिए थे. ईरान अब कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर अमेरिका से गुहार लगा रहा है कि प्रतिबंधों में छूट दी जाए, ताकि अन्य देश उसकी सहायता कर सकें.

अमेरिका में टाइगर को हुआ कोरोना वायरस, भारत में सभी चिड़ियाघर हाई अलर्ट पर

विश्वभर में लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले चुका कोरोना वायरस (Corona virus) अब जानवरों को भी अपनी चपेट में ले रहा है. अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के चिड़ियाघर (Bronx Zoo in New York) में एक टाइगर को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है.

अमेरिकी कृषि विभाग की राष्ट्रीय पशु चिकित्सा सेवा प्रयोगशाला के मुताबिक, ब्रॉन्क्स चिड़ियाघर (Bronx Zoo) में रखी गई एक मादा बाघिन में कोरोनो वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया है. बाघ में कोरोना वायरस संक्रमित होने का यह पहला मामला है.

भारत में सभी चिड़ियाघर हाई अलर्ट पर

भारतीय केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि देशभर के चिड़ियाघरों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी लक्षण / असामान्य व्यवहार के लिए सीसीटीवी के माध्यम से 24X7 जानवरों की निगरानी करें तथा न्यूयॉर्क के ब्रोंक्स ज़ू में बाघ को हुए कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर हाई अलर्ट पर रहें.

अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है . मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के कारण 1200 लोगों की मौत हो चुकी है. यह अब तक अमेरिका में एक दिन में कोरोना वायरस के करण हुई सबसे ज्यादा मौत हैं .

कोरोनो वायरस टेस्ट पॉजिटिव

वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के ब्रोंक्स ज़ू की एक ख़बर के मुताबिक, न्यूयॉर्क शहर के एक बाघ को कोरोनो वायरस टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है. चार साल की मादा मलय बाघ का नाम नादिया है. इसके साथ ही साथ तीन अन्य बाघ और तीन अफ्रीकी शेर में भी 'सूखी खाँसी' की शिकायत दर्ज की गई है. ब्रॉन्क्स चिड़ियाघर 16 मार्च से ही जनता के लिए बंद कर दिया गया था.

अन्य केस

इससे पहले बेल्जियम में एक बिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण का पहला मामला सामने आया था. बेल्जियम के हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस मामले की पुष्टि की है.

इसके पहले हांगकांग में दो कुत्तों को वायरस से संक्रमित पाया गया था. हांगकांग के कृषि मत्स्य और संरक्षण विभाग का कहना था कि ये ऐसा केस था, जिसमें इंसानों से जानवरों में संक्रमण फैलने की संभावना दिख रही थी.

पृष्ठभूमि

अमेरिका में कोरोना वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा है. यह अब इंसानों से जानवरों में पहुंच रहा है, ये बेहद गंभीर मुद्दा है.

UNSC ने कोविड-19 को लेकर पहली बैठक की, एकता बनाए रखने की आवश्यकता पर दिया जोर

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने 09 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी पर चर्चा करने के लिए पहली बार मुलाकात की. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने विश्वभर में कोरोना वायरस से उत्पन्न संकट पर चर्चा के लिए बुलायी गई अपनी पहली बैठक में कोविड -19 से प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता दिखाने और एकता बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया है.

लंबे समय के इंतजार के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की गुरुवार 09 अप्रैल 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई . सभी देशों को उम्मीद थी कि इस महामारी से निपटने के लिए बैठक से कुछ ठोस नतीजा निकलकर सामने आएगा. हालांकि इसका ठीक उल्टा हुआ . संयुक्त राष्ट्र में

चीन के राजदूत झांग जून ने कहा कि उनके देश को इस महमारी के लिए बलि का बकरा न बनाया जाए. उन्होंने कहा कि इस महासंकट से निपटने हेतु वैश्विक एकजुटता की जरुरत है.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस महामारी से निपटने के लिए महासचिव एंतोनियो गुतारेस के प्रयासों के प्रति भी समर्थन व्यक्त किया है. सुरक्षा परिषद ने कोविड-19 के प्रभाव को लेकर वीडियो-कांफ्रेंस के जरिये एक सत्र आयोजित किया था. संयुक्त राष्ट्र के इस प्रमुख अंग की अध्यक्षता अभी डोमिनिकन गणराज्य के पास है.

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख गुतारेस ने सत्र को संबोधित किया

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियो गुतारेस ने भी सत्र को संबोधित किया. संयुक्त राष्ट्र प्रमुख गुतारेस ने परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि 75 साल पहले संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से दुनिया अपने सबसे मुश्किल दौर में है. उन्होंने कहा कि इस बात का डर है कि विशेष रूप से विकासशील देशों और पहले से ही संघर्ष से जूझ रहे देशों में अभी इस महामारी का सबसे बुरा प्रभाव सामने आना बाकी है. गुतारेस ने जोर देकर कहा कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न शांति एवं सुरक्षा के खतरे को कम करने के लिए सुरक्षा परिषद की भागीदारी अहम होगी.

अमेरिका ने क्या कहा?

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भी अमेरिका का हमलावर रुख बरकरार रहा . अमेरिका के राजदूत ने मांग की कि इस वायरस की कहां पर उत्पत्ति हुई , इसकी जांच की जाए. अमेरिका ने साथ ही यह भी मांग की कि हेल्थ डेटा को सही समय पर शेयर किया जाए . अमेरिका और चीन के बीच नोक झोक के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस को आगे आना पड़ा . उन्होंने सुरक्षा परिषद से कोविड-19 महामारी से निपटने में एकजुट रहने का आह्वान किया.

एकजुट रहने की अपील की

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोरोना वायरस पर पहली बैठक में सुरक्षा परिषद से अपील करते हुए कहा कि इस मुश्किल समय में परिषद का एकजुट होकर इससे निपटने के लिए संकल्प लेना बहुत अहम है.

पृष्ठभूमि

दुनिया के लिए इस समय कोरोना वायरस महामारी से निपटना एक चुनौती बन गई है. इस वायरस की शुरुआत पिछले साल चीन के वुहान से हुई थी. यह वायरस अब लगभग पूरी दुनिया को प्रभावित कर चुका है. विश्वभर में कोरोना वायरस महामारी की चपेट में अब तक 16 लाख से अधिक लोग आ चुके हैं और 95,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है.

अमेरिका का बड़ा फैसला: ट्रंप ने WHO की फंडिंग रोकने का दिया आदेश

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 अप्रैल 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को अमेरिका से मिलने वाले वित्तपोषण (फंडिंग) पर रोक लगाने की घोषणा कर दी है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ को दी जाने वाली सालाना 50 करोड़ डॉलर तक की अमेरिकी धनराशि को रोकने की घोषणा की है.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वित्तपोषण रोके जाने की घोषणा करते हुए कहा कि दुनियाभर में फैलने से पहले चीन से शुरु हुए कोरोना वायरस की गंभीरता को डब्ल्यूएचओ ने छुपाया है . वहीं दूसरी संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के संशाधनों में कटौती करने का यह उचित समय नहीं है.

फंडिंग क्यों रोका गया?

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 अप्रैल 2020 को डब्ल्यूएचओ के फंडिंग पर रोक लगाने की घोषणा की और उस पर घातक कोरोना वायरस के प्रसार को कम करने को लेकर प्रबंधन में गंभीर गलती करने और जानकारी को छुपाने का आरोप लगाया है.

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि डब्ल्यूएचओ ने महामारी और अमेरिका के प्रति पारदर्शिता में रुकावट पैदा की है.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा?

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने प्रशासन को डब्ल्यूएचओ को दिए जाने वाले धन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि महमारी के कुप्रबंधन और कोरोना वायरस के प्रसार को छुपाने में विश्व स्वास्थय संगठन की भूमिका की जांच की जा रही है. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वह डब्ल्यूएचओ को दिए जाने वाले धन का उपयोग कैसे किया जाए इस पर चर्चा करेंगे.

डब्ल्यूएचओ को सबसे ज्यादा धन देने वाला देश

अमेरिका डब्ल्यूएचओ को सबसे ज्यादा धन देने वाला देश है. अमेरिका ने पिछले साल 40 करोड़ डॉलर का वित्तपोषण किया था. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका हर साल 40 करोड़ से 50 करोड़ डॉलर तक डब्ल्यूएचओ को देते हैं, जबकि चीन एक साल में लगभग चार करोड़ डॉलर का योगदान देता है या इससे भी कम. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि संगठन के प्रमुख प्रायोजक के रूप में अमेरिका का यह कर्तव्य है कि वह डब्ल्यूटीओ की पूर्ण जवाबदेही तय करे.

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने क्या कहा?

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने महामारी को लेकर कहा कि अब पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं है और इस पर विचार करें कि इस संकट से निकलने के लिए सभी लोगों को क्या करना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह समय एकजुटता का है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए यह समय इस वायरस और इसके विनाशकारी परिणामों को रोकने के लिए एकजुटता के साथ मिलकर काम करने का है.

अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर

अमेरिका में अब तक कोरोना वायरस (कोविड-19) के कारण संक्रमित लोगों की संख्या 6 लाख से अधिक पहुंच चुकी है. वहीं इस जानलेवा वायरस से अमेरिका में अब तक 25 हज़ार से अधिक लोगों की मौत हो गई है.

----------x----------x----------x----------

विज्ञान | तकनीक

नासा ने सनराइज़ मिशन की घोषणा की, जानें इसके बारे में सबकुछ

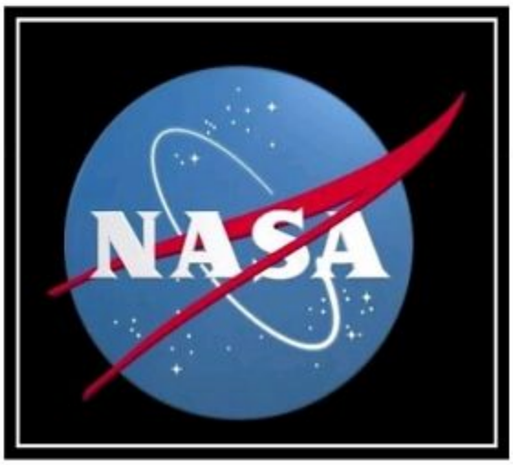

अमरीका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन (NASA) ने 30 मार्च, 2020 को एक नए मिशन-सनराइज की घोषणा की है जिसमें यह अध्ययन किया जाएगा कि सूर्य कैसे विशाल सौर कण तूफानों का निर्माण और प्रकाशन करता है.

सौर रेडियो इंटरफेरोमीटर अंतरिक्ष प्रयोग (सनराइज़) मिशन: इसका उद्देश्य वैज्ञानिकों को सौर मंडल के कामकाज को समझने में भी मदद करना है. यह भविष्य में चंद्रमा और मंगल पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को सौर तूफान से बचाने में भी मदद करेगा. यह मिशन 1 जुलाई, 2023 को शुरु होने की उम्मीद जताई जा रही है.

सनराइज़ मिशन के प्रमुख उद्देश्य

- सनराइज़ मिशन इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा कि सूर्य का विकिरण अंतरिक्ष पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है.
- यह भविष्य में चंद्रमा या मंगल ग्रह से संबंधित विभिन्न मिशनों पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों का सौर तूफानों से बचाव करेगा.
- यह सूर्य के स्पेक्ट्रम अर्थात वर्णक्रम के उस हिस्से का भी अध्ययन करेगा जो आयनमंडल के कारण पृथ्वी पर नहीं देखा जा सकता है.
- यह सूर्य के बारे में वह जानकारी जुटाने में भी सहायता करेगा जो अन्य सौर जांच यंत्रों - पार्कर सोलर प्रोब, सोलर ऑर्बिटर और ग्राउंड-बेस्ड डैनियल के. इनौय सौर दूरबीन से हासिल नहीं हो सकती है.

सनराइज़ मिशन का महत्त्व

सूर्य के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के साथ यह भी पता लगाना कि सूर्य कैसे अंतरिक्ष में मौसम की घटनाओं को प्रभावित करता है. इससे अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष यान पर अंतरिक्ष के मौसम के प्रभावों को कम करना आसान होगा.

सनराइज़ मिशन: प्रमुख विशेषताएं

- सन राइज़ मिशन में छह क्यूबसैट्स लगे होंगे जो एक बहुत बड़ी रेडियो दूरबीन के तौर पर काम करेंगे.
- यह मिशन एक पेलोड ऑर्बिटल डिलीवरी सिस्टम (PODS) से जुड़ा होगा और अपने 6 क्यूबसैट्स को जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट (GEO) में तैनात करेगा. ये सभी 6 क्यूबसैट्स एक दूसरे से कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी पर उड़ेंगे.
- ये सभी क्यूबसैट्स सौर सक्रियता से कम आवृत्ति के उत्सर्जन की रेडियो छवियों का निरीक्षण एक साथ करेंगे और उन्हें नासा के गहन अंतरिक्ष नेटवर्क के माध्यम से साझा करेंगे.
- ये क्यूबसैट्स पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर उड़ेंगे ताकि रेडियो संकेत अवरुद्ध न हों और सन राइज़ इन रेडियो संकेतों का निरीक्षण करेगा.
- ये सभी क्यूबसैट्स उस स्थान को इंगित करने के लिए 3 डी मानचित्र बनाएंगे जहां विशाल कण सूर्य पर उत्पन्न होते हैं और जब वे विशाल कण अंतरिक्ष में बाहर की ओर बढ़ते हैं तो कैसे विकसित होते हैं. इस जानकारी से यह निर्धारित करने में मदद करेगी कि विकिरण के इन विशाल जेटों की शुरुआत कैसे होती है और कैसे ये तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं.
- ये सभी क्यूबसैट्स सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र से निकलने वाली रेखाओं के विभिन्न ग्रहों के बीच अंतरिक्ष में पहुंचने के पैटर्न के संबंध में भी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करेंगे. यह मैपिंग पहली बार की जाएगी.
- सनराइज मिशन को मैक्सार द्वारा निर्मित वाणिज्यिक उपग्रह/ सैटॅलाइट द्वारा राइड शेयर मिशन के रुप में लॉन्च करने की पेशकश की गई है. इसे एक वाणिज्यिक रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किए जाने की संभावना है.

नोट: यह सनराइज मिशन मार्स क्यूब वन (मार्को) और डीएआरपीए हाई-फ्रीक्वेंसी रिसर्च (डीएचएफआर) की सफलता के कारण संभव हो सका है. इन मिशनों में उन तकनीकों का इस्तेमाल हुआ था जिनका उपयोग सन राइज़ मिशन में किया जाएगा और इस मिशन के लिए इन तकनीकों को कम लागत, कम जोखिम वाले विकल्प के तौर पर तैयार किया गया है. इन सभी क्यूबसैट्स में सॉफ्टवेयर-डिफाइंड रेडियो और जीपीएस लगे होंगे.

सनराइज़ मिशन की पृष्ठभूमि

नासा ने अपने एक्सप्लोरर/ खोजकर्ता कार्यक्रम के एक हिस्से के तौर पर मिशन ऑफ़ ऑपर्चुनिटी प्रोग्राम के तहत 11 महीने की कॉन्सेप्ट स्टडी का संचालन करने के लिए अगस्त 2017 में दो मिशन निर्धारित किये थे. सन राइज़ मिशन इनमें से एक मिशन है.
नासा ने फरवरी 2019 में इस कार्यक्रम को तैयार करने के अध्ययन के लिए एक अतिरिक्त वर्ष को मंजूरी दी थी. अमरीका की अंतरिक्ष एजेंसी को मार्च 2020 में 62.6 मिलियन डॉलर प्रदान किये गए ताकि सन राइज़ मिशन का डिजाइन तैयार करके इसका निर्माण जाए और निर्धारित समय पर लॉन्च किया जा सके. इस मिशन को जुलाई 2023 में लॉन्च किया जा सकता है.
सन राइज़ से संबंधित सारी व्यवस्था नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी (JPL) द्वारा पासाडेना, कैलिफोर्निया में की जा रही है.

नासा के ऑपर्च्युनिटी मिशन्स

नासा के मिशन्स ऑफ ऑपर्च्युनिटी के तहत अंतरिक्षयान लॉन्च करने से संबंधित अपेक्षाकृत कम लागत वाले मिशन शामिल हैं जिन्हें अधिकतम वैज्ञानिक अध्ययनों को फिर से शुरु करने के लिए पूर्व स्वीकृति प्राप्त है.

सनराइज मिशन को मैक्सार द्वारा निर्मित वाणिज्यिक सैटॅलाइट द्वारा राइड शेयर मिशन के रूप में लॉन्च करने की पेशकश की गई है और इसमें पेलोड ऑर्बिटल डिलीवरी सिस्टम या PODS लगा होगा. मेजबान अंतरिक्षयान ऑर्बिट में जाने के बाद अन्य छह अंतरिक्ष यान तैनात करेगा और फिर अपना मुख्य मिशन शुरु करेगा.

नासा के मिशन्स ऑफ ऑपर्च्युनिटी नासा के सबसे पुराने और निरंतर जारी कार्यक्रम - खोजकर्ता कार्यक्रम का एक हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष में बार-बार, कम लागत वाली यात्रा के अवसर

प्रदान करना है. एक्सप्लोरर कार्यक्रम के तहत पहला प्रक्षेपण जनवरी, 1958 में अमेरिका के पहले उपग्रह के साथ हुआ था.

डीएसटी ने कोविड-19 महामारी से लड़ने हेतु रसायन मुक्त चांदी आधारित कीटाणुनाशक विकसित किया

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) और जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित पुणे के एक स्टार्टअप वेइनोवेट बायोसोल्यूशंस ने अल्कोहल के बिना जलीय-आधारित कोलाइडल चांदी सोल्यूशन तैयार किया है.इसे हाथों और पर्यावरणीय सतहों को कीटाणुरहित करने के लिए नैनोएगसाइड टेक्नोलॉजी से बनाया गया है.

यह तरल गैर-ज्वलनशील और खतरनाक रसायनों से मुक्त है और महामारी के ट्रांसमिशन की प्रमुख विधि–सम्पर्क से होने वाले संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु एक प्रभावी सैनिटाइजर हो सकता है. इससे स्वास्थ्य पेशेवरों और अन्य संक्रमित लोगों की रक्षा हो सकती है.

मुख्य बिंदु:

वाइनोवेट बायोसोल्यूशंस का कोलाइडल सिल्वर सॉल्यूशन, जो वायरल नेगेटिव-स्ट्रैंड आरएनए और वायरल बडिंग के संश्लेषण को रोकने हेतु सिल्वर नैनोपार्टिकल्स की क्षमता पर आधारित है.

यह खतरनाक रसायनों से मुक्त है और इसमें अल्कोहल-आधारित कीटाणुनाशकों की तुलना में ज्वलनशीलता का कोई खतरा नहीं है.

इस सॉल्यूशन का प्रयोगशाला परीक्षण हुआ है, और निर्माताओं ने परीक्षण लाइसेंस प्राप्त कर लिया है.

इसे छोटे पैमाने पर कोलाइडल सिल्वर को संश्लेषित करने और पांच लीटर तक के स्केल-अप बैच पर प्रारंभिक कार्य दोबारा तैयार करने के लिए किया जा रहा है.

वाइनोवेट बायोसोल्यूशंस के संस्थापक ने क्या कहा?

वाइनोवेट बायोसोल्यूशंस के संस्थापकों में से एक डॉ. मिलिंद चौधरी ने कहा कि हम हैंड सैनिटाइजेशन और कीटाणुशोधन की मांग को पूरा करने के लिए हमारी निर्माण व्यवस्था के साथ प्रति दिन मुख्य रुप से 200 लीटर कोलाइडल चांदी के घोल का निर्माण करने का लक्ष्य बना रहे हैं.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कहा कि नैनोकण थेरानोस्टिक्स (थेरेपी और डॉयग्नोस्टिक्स) से कीटाणुशोधन से लेकर इमेर्जिंग तक कोविड -19 से संबंधित विभिन्न मुद्दों के प्रभावी समाधान के रुप में तेजी से उभर रहे हैं. नैनोकणों की प्रासंगिकता उनके आकार के कारण है, जो कोविड-19 वायरस से तुलनीय है और कार्यशीलता की अधिकता जैसे लक्ष्य बनाना और दवा वितरण आवश्यकतानुसार किया जा सकता है.

सिल्वर नैनोकण: सिल्वर नैनोकण को एक प्रभावी एंटीवायरल पाया गया है जो एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, हरपीज सिम्प्लेक्स वायरस, इन्फ्लूएंजा वायरस जैसे घातक वायरसों के खिलाफ काम करता है. हाल ही की रिपोर्टों में वायरल नेगेटिव-स्ट्रैंड आरएनए और वायरल बडिंग के संश्लेषण को रोककर कोरोनो वायरस के प्रसार को रोकने में ग्लुटाथियोन कैप्ड-एजी2एस एनसी (सिल्वर नैनोक्लस्टर्स) की भूमिका का सुझाव दिया गया है.

कोलाइडल सिल्वर: कोलाइडल सिल्वर जिस पर वाइनोवेट बायोसोल्यूशन के सैनिटाइज़र की तकनीक आधारित है, वह सतह ग्लाइकोप्रोटीन को अवरुद्ध करके आरएनए प्रतिकृति और संक्रामकता को रोककर कोविड -19 को फैलने से रोक सकता है. कोलाइडल सिल्वर बनाने की प्रक्रिया के लिए एक भारतीय पेटेंट दायर किया गया है, और हैंड सैनिटाइज़र और कीटाणुनाशक बनाने के लिए एक परीक्षण लाइसेंस प्रदान किया गया है.

नासा का नया उपग्रह ज्वालामुखी और भूकंप की चेतावनी देगा

राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अन्तरिक्ष प्रशासन (नासा) का एक नया उपग्रह (सैटेलाइट) ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप के शुरुआती चेतावनी संकेत दे सकता है. इस उपग्रह से उपलब्ध आंकड़े उस क्षेत्र की पहचान करने में मदद करेंगे जहां ऐसे किसी संकट के दौरान आपदा राहत पहुंचाई जानी चाहिए.

नासा ने वर्ष 2020 के शुरू में 1200 से अधिक क्यूबसैट अंतरिक्ष में छोड़े थे. इन 1200 क्यूबसैट्स में से, 80 क्यूबसैट्स लॉन्च के दौरान ही नष्ट हो गए थे, लेकिन 1100 से अधिक क्यूबसैट्स अभी भी पृथ्वी की कक्षा में स्थित हैं. ये क्यूबसैट्स अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए बनाए गए एक प्रकार के छोटे उपग्रह हैं.

महत्व

क्यूबसैट इमेजिंग रडार फॉर अर्थ साइंसेज (CIRES) को आपदा से निपटने के लिए निर्णयकर्ताओं को तैयारी करने में मदद प्रदान करने के लिए बनाया जायेगा.

इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक एपर्चर रडार (InSAR) से उपलब्ध डाटा भी आपदा के स्थान की पहचान करने में मदद कर सकता है.

ज्वालामुखी और भूकंप की भविष्यवाणी कैसे काम करेगी?

भूकंपों के लिए, CIRES के नए किस्म के रडार भूकंप के आने से पहले ही इसके खतरे को भांप सकते हैं.

किसी ज्वालामुखी विस्फोट से पहले उभार घटना होती है. मैग्मा जमा होता है और जिसके कारण जमीन थोड़ी-सी ऊपर की तरफ़ उभरती है. InSAR इस उभार का निरीक्षण कर सकता है और उस विशेष क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में पूर्व-चेतावनी दे सकता है.

अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के एक भूभौतिकीविद् केली एंडरसन के अनुसार, 'यद्यपि, यह अनुमान लगाना मुश्किल होगा कि यह भावी विस्फोट कितना लंबा या बड़ा होगा'.

नासा के बारे में:

राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अन्तरिक्ष प्रशासन (नासा) की स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी और यह संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार का एक स्वतंत्र निकाय है.

यह नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के साथ-साथ वैमानिकी एवं अन्तरिक्ष तकनीकी अनुसंधान से जुड़े सारे कामकाज संभालता है.

नासा विज्ञान का उद्देश्य पृथ्वी अवलोकन प्रणाली के माध्यम से पृथ्वी की बेहतर समझ, पूरे सौर मंडल में स्थित अन्य निकायों की खोज करने के साथ विभिन्न संबंधित कार्यक्रमों और गहन अवलोकनों के माध्यम से विभिन्न खगोल भौतिकी विषयों के बारे में अनुसंधान करना है.

भारतीय अनुसंधानकर्ताओं ने कोविड – 19 के जीनोम अनुक्रमण पर काम शुरू किया

जीनोमिक्स और एकीकृत जीवविज्ञान संस्थान (IGIB), नई दिल्ली और कोशिकीय और आणविक जीवविज्ञान केंद्र (CCMB), हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने नोवल कोरोना वायरस के जीनोम अनुक्रमण पर अनुसंधान कार्य करना शुरु कर दिया है. ये दोनों ही संस्थान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र (ICSR) के सहयोगी संस्थान हैं.

यह एक नया वायरस है और इस अनुसंधान का उद्देश्य इस वायरस के विभिन्न पहलुओं के बारे में सटीक जानकारी हासिल करना है. यह अध्ययन वायरस के विकास को समझने के साथ यह समझने में भी मदद करेगा कि यह वायरस कितनी तेजी से फ़ैल सकता है. जिन रोगियों में कोविड – 19 का परीक्षण सकारात्मक पाया गया है, उनसे नमूने प्राप्त करके इस वायरस के अनुक्रमण पर अनुसंधान किया जा सकता है.

उद्देश्य:

नोवल कोरोना वायरस वायरस का एक नया रुप है. इस अध्ययन से वायरस के विकास को समझने में मदद मिलने के साथ ही यह भी जानकारी मिलेगी कि, यह वायरस कितना विविध है और यह कितनी तेजी से विकसित हो सकता है और इस वायरस के भावी पहलू क्या हो सकते हैं.

आखिर यह जीनोम अनुक्रमण की विधि क्या है?

जीनोम अनुक्रमण विधि ही किसी भी जीव के जीनोम के पूर्ण डीएनए अनुक्रमण को निर्धारित करती है. इस अनुसंधान में सही परिणाम पाने के लिए, बहुत बड़ी संख्या में नमूनों के अध्ययन की आवश्यकता होती है. पर्याप्त डाटा के बिना, दिए गए निष्कर्ष गलत या अपूर्ण हो सकते हैं.

जीनोम अनुक्रमण विधि: मुख्य विशेषताएं

- जीनोम अनुक्रमण पर अनुसंधान कार्य करने के लिए बड़ी संख्या में नमूनों की आवश्यकता होती है, इसलिए जिन रोगियों के परीक्षण सकारात्मक पाए गए हैं, उनके नवीनतम नमूने अनुक्रमण केंद्रों को भेजे गए हैं.
- प्रत्येक संस्थान के तीन से चार लोग जीनोम अनुक्रमण पर अनुसंधान का काम कर रहे हैं.
- अगले 3-4 हफ्तों में, शोधकर्ता 200-300 आइसोलेट्स प्राप्त करने में सक्षम होंगे. यह जानकारी वायरस के व्यवहार के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालने में मदद करेगी.
- व्यवहार का निर्धारण करने के लिए, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (NIV) से भी एक वायरस देने का अनुरोध किया गया है जिसे अलग स्थान से हासिल किया गया हो.
- यह पूरा अनुसंधान इस वायरस के वंश क्रम को निर्धारित करने में मदद करेगा.
- विभिन्न संस्थानों ने अपनी परीक्षण क्षमता भी बढ़ा दी है और बड़े पैमाने पर लोगों की जांच की जा रही है. इससे सकारात्मक मामलों की पहचान करने में मदद मिलेगी.

किसान वैज्ञानिक ने की बायोफोर्टिफाइड गाजर विकसित

एक किसान वैज्ञानिक ने मधुबन गाजर को विकसित किया है जो उच्च बीटा-कैरोटीन और लोह तत्त्व के साथ एक बायोफोर्टिफाइड किस्म की गाजर है. श्री वल्लभभाई वासराममभाई मारवानिया एक किसान वैज्ञानिक हैं जो गुजरात के जूनागढ़ जिले में रहते हैं.

गाजर की यह किस्म गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में 200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में लगाई गई है और वहां के किसानों की आय का मुख्य स्रोत बनकर उस क्षेत्र के 150 से अधिक स्थानीय किसानों को लाभान्वित कर रही है. पिछले 3 वर्षों से इसकी खेती गुजरात की 1000 हेक्टेयर से अधिक भूमि के साथ-साथ अन्य राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी की जा रही है.

महत्व:

मधुबन गाजर बायोफोर्टिफाइड किस्म की एक गाजर है जो अत्यधिक पौष्टिक है और इसे लोह तत्त्व (276.7 मिलीग्राम/ किग्रा) और उच्च बीटा-कैरोटीन तत्त्व (277.75 मिलीग्राम/ किग्रा) के साथ चयन विधि के माध्यम से विकसित किया गया है.

मुख्य विशेषताएं

- गाजर की इस किस्म का उपयोग कई मूल्य वर्धित उत्पादों जैसे अचार, जूस और गाजर के चिप्स बनाने के लिए किया जा रहा है.
- वर्ष 2016-2017 के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान, राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान (NIF), भारत द्वारा गाजर की इस किस्म पर सत्यापन परीक्षण किए गए. ये सभी परीक्षण राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित किए गए थे.
- इन परीक्षणों में गाजर की इस मधुबन गाजर किस्म में काफी उच्च उपज (74.2 t/ ha) (t/ ha अर्थात 01 टन/ प्रति हेक्टेयर) पाई गई.

गाजर की इस किस्म का विकास कैसे हुआ?

वल्लभभाई वासरामभाई मारवानिया ने वर्ष 1943 में यह जान लिया था कि दूध की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए स्थानीय गाजर की एक किस्म का इस्तेमाल चारे के तौर पर किया जाता है. उन्होंने विशेष रूप से उसी किस्म की गाजर की खेती करनी शुरु कर दी और इस गाजर को बाजार में अच्छी कीमत पर बेचना शुरु कर दिया. तभी से, वे और उनका परिवार गाजर की इस उच्च उपज किस्म के विकास और संरक्षण पर काम कर रहे हैं.

वल्लभभाई वासराममभाई मारवानिया को मिले हैं ये पुरस्कार:

गाजर के क्षेत्र में वल्लभभाई वासराममभाई मारवानिया के असाधारण योगदान के लिए, वर्ष 2019 में उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था. वर्ष 2017 में, भारत के राष्ट्रपति द्वारा श्री वल्लभभाई वासराममभाई मारवानिया को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया.

भारतीय चमगादड़ की दो प्रजातियों में मिला बैट कोरोना वायरस: ICMR

विश्वभर के वैज्ञानिक इस खोज में लगे हैं कि कोविड-19 का वायरस इंसानों तक किस जीव के जरिए पहुंचा. इसी बीच भारत के वैज्ञानिकों ने देश के चार राज्यों में चमगादड़ों के नमूनों में बैट कोरोना वायरस (बीटी सीओवी) होने की पुष्टि की है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह कोरोना वायरस कोविड-19 बीमारी के कोरोना वायरस सार्स सीओवी2 से मिलता जुलता हो सकता है.

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) ने पहली बार एक अलग किस्म के कोरोना वायरस की पहचान की है. ये वायरस, चमगादड़ में पाया जाने वाला बैट कोरोना वायरस है. आईसीएमआर का यह अध्ययन इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित हुआ है. डॉक्टर प्रज्ञा यादव के नेतृत्व में हुए इस शोध का उद्देश्य यह जानना है कि कोरोना वायरस की प्रजाति के कौन से और वायरस चमगादड़ या अन्य जीवों में मौजूद हो सकते हैं.

इन राज्यों में मिला वायरस

इस शोध में वैज्ञानिकों ने भारत के दस राज्यों में मौजूद दो प्रजाति की चमगादड़ के सैम्पल लिए थे. इनमें पिटरोपस एवं रोसेट्स प्रजाति के चमगादड़ों के नमूने लिए गए. वैज्ञानिकों ने भारत के 4 राज्यों में चमगादड़ों में बैट कोरोना वायरस की पुष्टि की है. केरल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु और पुडुचेरी में चमगादड़ से लिए गए नमूनों में बैट कोरोना वायरस मिलने की पुष्टि हुई है. इनमें कर्नाटक, चंडीगढ़, उड़ीसा, पंजाब, गुजरात, तेलंगाना में चमगादड़ में बैट कोरोना वायरस नहीं मिला है.

कोरोना वायरस इंसानों तक कैसे पहुंचा

मालूम हो कि पहले भी ऐसे कई दावे सामने आ चुके हैं कि चमगादड़ों के जरिये ही कोरोना वायरस इंसानों तक पहुंचा है. चीन में लगभग हर तरह के जंगली जीवों को खाने का प्रचलन है. वहां एक

बड़ी आबादी चमगादड़ भी खाती हैं. हालांकि, इस बात के अभी भी कोई स्पष्ट वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं हैं कि ये खतरनाक वायरस, चमगादड़ों के जरिये ही इंसानों तक पहुंचा है.

आइसीएमआर ने क्या कहा?

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के भारतीय शोध पत्र में प्रकाशित इस शोध में दावा किया गया है कि इस बात के कोई साक्ष्य या शोध मौजूद नहीं कि चमगादड़ में पाया जाने वाला यह वायरस इंसानों को संक्रमित कर सकता है. शोधकर्ता और पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआइवी) की वैज्ञानिक डॉ. प्रज्ञा डी. यादव के मुताबिक केरल, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु में रोसेटस और पेरोपस नामक प्रजाति के 25 चमगादड़ों में कोरोना के वायरस पाए गए हैं.

----------x----------x----------x----------

राज्य

भीलवाड़ा मॉडल क्या है? इससे कैसे कंट्रोल हुआ कोविड-19

सरकार देशभर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने हेतु हर संभव प्रयास करने में जुटी है. देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. कोरोना वायरस को फैलने से रोकने हेतु केंद्र और राज्य सरकारें हर संभव कदम उठा रही है. जनता कर्फ्यू लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन लगाए जाने के बाद भी कोरोना वायरस के पॉजीटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रहा है.

राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल कोरोना वायरस से निपटने हेतु देश के सामने एक उदाहरण साबित हो सकता है. भीलवाड़ा में जब पहली बार कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस सामने आए तो ऐसा लगा कि जैसे भीलवाड़ा भारत का दूसरा इटली बनने जा रहा है. हालांकि, राजस्थान सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और पूरे शहर में कर्फ्यू लगाकर बॉर्डर सील कर दिया. कोरोना से लड़ने के लिए भीलवाड़ा मॉडल को देश में लागू किया जा सकता है.

भीलवाड़ा मॉडल को काफी सराहा

भारत सरकार ने राजस्थान सरकार के भीलवाड़ा मॉडल को काफी सराहा है और यह ब्योरा मांगा है कि किस तरह से भीलवाड़ा शहर में कोरोना पॉजिटिव लोगों का इलाज किया गया और कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका गया.

भीलवाड़ा मॉडल क्या है?

राजस्थान के भीलवाड़ा में कोरोना वायरस से निपटने को लेकर अपनाई गई नीति पूरे देश में लागू हो सकती है. राजस्थान के भीलवाड़ा में एक डॉक्टर के संक्रमित होने के बाद वहां तेजी से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी, लेकिन बाद में यह आंकड़ा 27 मरीजों से अधिक नहीं बढ़ा.

पॉजिटिव मरीज सामने आते ही भीलवाड़ा में कर्फ्यू लगाकर सीमाएं सील कर दी गईं. भीलवाड़ा में जिले के सभी निजी अस्पतालों और होटलों को अधिगृहीत कर लिया गया.

लॉकडाउन कि सख्ती से पालना और घर-घर स्क्रीनिंग की गई. इसके अतिरिक्त जनप्रतिनिधियों, मीडिया और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी शहर में प्रवेश नहीं दिया गया. जिला प्रशासन और पुलिस के भी कुछ ही अधिकारी शहर में गए.

भीलवाड़ा में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने पर जोर दिया गया. इन सबके चलते भीलवाड़ा में कोरोना वायरस के मामले आगे नहीं बढ़े. भीलवाड़ा में कई संक्रमित मरीज ठीक हो गए. भीलवाड़ा में पिछले 17 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भीलवाड़ा में लगभग 18 लाख लोगों की स्क्रीनिंग का काम 10 दिनों के अंदर किया गया. इसके अतिरिक्त जितने भी लोग सर्दी जुकाम के मरीज थे सभी को घरों से निकालकर क्वारनटीन किया गया.

राजस्थान सरकार ने भीलवाड़ा के सभी फाइव स्टार और थ्री स्टार होटल, रिजॉर्ट और प्राइवेट अस्पतालों का अधिग्रहण किया और यहां पर कोरोना के लक्षण पाए गए लोगों को क्वारनटीन किया. भीलवाड़ा में 27 लोगों में से अब सिर्फ सात लोग कोरोना पॉजिटिव बचे हैं बाकी 20 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं.

केंद्र सरकार ने विस्तृत जानकारी मांगी

केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने प्रदेश के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता से भीलवाड़ा मॉडल को लेकर विस्तृत जानकारी मांगी. केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार के भीलवाड़ा मॉडल को काफी सराहा है और यह ब्योरा मांगा है कि किस तरह से भीलवाड़ा शहर में कोरोना पॉजिटिव लोगों का इलाज किया गया और कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका गया. मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने हाल ही में सीएम अशोक गहलोत की समीक्षा बैठक में इसकी जानकारी दी. केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने मुख्य सचिव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी.

यूपी में नोएडा और लखनऊ समेत 15 जिले पूरी तरह से सील, जानें इसके बारे में सबकुछ

उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने लॉकडाउन के बावजूद कई इलाकों में कोरोना मरीजों की बढ़ी संख्या को देखते हुए अब सख्त कदम उठाया है. प्रदेश के पंद्रह जिलों में उन 104 क्षेत्रों को हॉट स्पॉट के रुप में चिन्हित किया है, जहां छह या उससे अधिक संक्रमित मरीज हैं.

यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के 15 जिलों को सील कर दिया है. इन 15 जिलों में लखनऊ के साथ वे सभी जिले शामिल हैं जहां लगातार जमातियों या उनके संपर्क में आए लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है.इस दौरान यहां कर्फ्यू जैसा प्रतिबंध रहेगा.

घर के बाहर कदम रखने पर पाबंदी होगी. हर आवश्यक वस्तु की होम डिलीवरी की जाएगी. अब उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति 30 अप्रैल तक बिना मास्क के बाहर नहीं निकल सकेगा.

यूपी सरकार ने यह निर्णय 13 अप्रैल तक लिया है. वे उसके बाद इस निर्णय की फिर से समीक्षा करेगी. यह आदेश आज (8 अप्रैल 2020) रात 12 बजे से लागू होगा. इस दौरान इन जिलों में खाने-पीने की दुकाने भी नहीं खुलेंगी उसकी जगह आवश्यक वस्तुओं की होम डिलिवरी जारी रहेगी.

पूरी तरह से होंगे सील

योगी सरकार ने यह निर्णय राज्य में बढ़ते कोरोना केसों को कम करने के लिए किया जाएगा. इन जिलों में वही लोग घर से बाहर निकल सकते हैं जिनके पास कर्फ्यू पास होगा. इस दौरान खाने-पीने की दुकाने भी नहीं खुलेगी. मगर जरुरत की चीजों की होम डिलिवरी जारी रहेगी.

इन शहरों को किया गया सील

योगी सरकार ने आगरा, शामली, मेरठ, बरेली, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, बस्ती, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, महाराजगंज, सीतापुर, बुलंदशहर, फिरोजाबाद और नोएडा को पूरी तरह से सील करने का फैसला किया है. यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने पुष्टि की है.

कोरोना का कहर जारी, पंजाब सरकार ने 01 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन

पंजाब सरकार ने 10 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में 01 मई तक कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पंजाब में कोरोना के अब तक कुल 130 मामले सामने आए हैं. इनमें से 4 जहां पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, वहीं अब तक 10 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है.

पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर राज्य में मास्क पहनना भी 09 अप्रैल 2020 से ही अनिवार्य कर दिया है. पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इसकी जानकारी दी.

मुख्यमंत्री ने अपने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि पंजाब में अब मास्क पहनना अनिवार्य है. जब भी आप किसी आपात स्थिति में या आवश्यक वस्तुओं के लिए घर से बाहर निकलें तो मास्क जरुर पहनें.

01 मई तक कर्फ्यू

पंजाब के 17 जिले अब तक कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं. पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इसी को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा घोषित 21 दिन के लॉकडाउन को 01 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है. सरकार का मानना है कि यही एक तरीका है जिससे वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोका जा सकता है.

जरुरी चीजों की ऑनलाइन डिलिवरी

हालांकि पंजाब में 01 मई तक चलने वाली बंदी लॉकडाउन से सख्त होगी और इसमें लोगों को आपात स्थित के अलावा किसी भी हाल में घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी. सरकार जरुरी चीजों की आपूर्ति ऑनलाइन डिलिवरी के माध्यम से सुनिश्चित करेगी.

यूपी को COVID-19 के लिए पुल परीक्षण शुरू करने की अनुमति मिली

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (ICMR) ने उत्तर प्रदेश (यूपी) को कोविड -19 के लिए पूल परीक्षण शुरु करने की मंजूरी दे दी है. यह भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो इस विधि को क्रियान्वित करेगा. पूल परीक्षण विधि में, स्वैब के कई नमूनों को एक साथ रखकर उनका परीक्षण किया जाता है. इस प्रक्रिया के क्रियान्वयन से कोविड -19 के निदान को तेज गति से करने में मदद मिलेगी.

उत्तर प्रदेश के प्रधान सचिव ने कहा कि, उनकी सरकार भी इस विधि का उपयोग करने के लिए प्रोटोकॉल के संबंध में निर्णय ले रही थी और इसे 14 अप्रैल से लागू किया जाना था. हमारे देश में महाराष्ट्र इस परीक्षण विधि का इस्तेमाल करने के लिए ICMR से अनुमति लेने वाला दूसरा राज्य बन गया है.

पूल परीक्षण विधि क्या है?

नमूना संग्रह का पूल परीक्षण एक एकल RTPCR (रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन) का इस्तेमाल करके किया जाता है. इस विधि के तहत, कई स्वैब नमूनों को एक साथ रखकर उनका परीक्षण किया जाता है. अगर इन नमूनों का परिणाम नकारात्मक आता है, तो इससे पता चलता है कि संबद्ध स्वैब समूह के सभी नमूने नकारात्मक हैं. लेकिन अगर एक भी संग्रह का परिणाम सकारात्मक पाया जाता है, तो उन नमूनों में से प्रत्येक स्वैब का व्यक्तिगत रुप से परीक्षण किया जाएगा.

पूल परीक्षण विधि: मुख्य विशेषतायें

- यह विधि भारत के लिए फायदेमंद होगी जो परीक्षण किटों के साथ-साथ बुनियादी ढांचे की कमी से भी जूझ रहा है. इससे संसाधनों के बेहतरीन इस्तेमाल के साथ-साथ कोविड -19 स्क्रीनिंग भी बढ़ेगी.
- इस विधि का इस्तेमाल इस महामारी के अप्रत्यक्ष सामुदायिक प्रसार और विशाल स्तरीय संक्रमण के दौरान किया गया है.
- इज़राइल में शोधकर्ताओं ने यह भी महसूस किया कि, कोविड -19 के लिए 64 लोगों के संयुक्त नमूनों के परीक्षण ने स्क्रीनिंग प्रक्रिया को तेज कर दिया था और इसकी लागत भी काफी कम आई थी.

उत्तर प्रदेश में परीक्षण के लिए उपलब्ध इन्फ्रास्ट्रक्चर:

इस समय उत्तर प्रदेश में 10 प्रयोगशालाएं हैं जो प्रति दिन लगभग 2000 नमूनों का परीक्षण कर रही है. यह राज्य 14 नई प्रयोगशालाओं को भी इस काम में शामिल कर रहा है और इससे स्क्रीनिंग के बुनियादी ढांचे में भी इजाफ़ा होगा.

उत्तर प्रदेश में गत रविवार तक 550 मामले दर्ज किए गए थे. इसमें से 47 मरीज़ों को ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई है. इस राज्य में कोरोना वायरस से अब तक कुल 5 मौतें हुई हैं. पीलीभीत में कोविड -19 के कुल 2 मामले सामने आये हैं और रिपोर्ट के अनुसार वे दोनों मरीज़ अब ठीक हो चुके हैं और फिर इसके बाद कोई नया मामला सामने नहीं आया है.

---------x----------x----------x-------

- अनुराग श्रीवास्तव के पास इथियोपिया और अफ्रीकी संघ में भारत के राजदूत के रूप में काम करने का उनके पास लंबा अनुभव है.
- अनुराग श्रीवास्तव ने उच्च शिक्षा दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, उनके पास इंजीनियरिंग और बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री है.
- उन्होंने पढ़ाई पूरी करते ही कॉरपोरेट सेक्टर में अपनी सेवाएं देना शुरु कर दिया था. उन्होंने नौकरी के साथ ही पब्लिक कमीशन की तैयारी करना शुरु कर दिया था.
- उनका चयन साल 1999 में भारतीय विदेश सेवा के लिए हुआ. अनुराग श्रीवास्तव ने यूनाइटेड किंगडम की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिप्लोमैटिक स्टडीज में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लिया है.
- वे इससे पहले जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के सदस्य भी रहे हैं. इथोपिया के राजदूत बनाए जाने से अनुराग श्रीवास्तव नई दिल्ली के फाइनेंस डिविजन के हेड के पद पर काम कर चुके हैं.
- वे कोलंबो में भारतीय हाई कमीशन के पॉलिटिकल विंग के चीफ के पद पर भी रहे हैं. अनुराग श्रीवास्तव एकस्टर्नल पब्लिसिटी डिवीजन में अंडर सेक्रेटरी भी रह चुके हैं.

अगले 6 महीनों में दिल्ली में हो सकते हैं 1. 5 मिलियन से ज्यादा कोरोना वायरस के केस:

ICMR स्टडी

इंडियन कॉउन्सिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च (ICMR) द्वारा की गयी ऑप्टिमिस्टिक सेनारिओ स्टडी के अनुसार दिल्ली में सिम्पटोमैटिक कोरोना वायरस के केसेस अगले दो साल में 20,000 तक हो सकते हैं. दूसरा अध्ययन यह भी है कि अगले 6 महीनों में यह केसेस 1.5 मिलियन तक जा सकते हैं.

रिसर्च पेपर में दो तरह के शोध निकल कर आएं हैं- ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक, जो कि भारत के 4 बड़े राज्यों- दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में इसके फैलने की स्थिति दिखाता है.

ICMR द्वारा की गयी स्टडी के अनुसार भारत COVID - 19 के तीसरे चरण में पहुँच सकता है जो कि कम्यूनिटी ट्रांसमिशन है. समय पर बीमारी का पता लगाना और मरीज़ों का quarantine होना यह निर्धारित करेगा की स्टेज- 3 कब होगा.

ICMR स्टडी- ऑप्टिमिस्टिक सेनारिओ

ICMR स्टडी द्वारा की गयी ऑप्टिमिस्टिक सेनारिओ में, सिम्पटोमैटिक लोगों का पता लगाने में और उन्हें quarantine में भेजने में कामयाबी हासिल होगी और देश में यह वायरस 62 परसेंट तक कम हो जायेगा. इस स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए- बीमारी का पता लगाने के लिए स्क्रीनिंग और quarantine में और सुधार लाने की ज़रूरत है. खासकर असिम्पटोमैटिक मरीज़ों की स्क्रीनिंग जो इस महामारी को चरम तक नहीं जाने देगी.

ICMR स्टडी: पेसिमिस्टिक सेनारिओ

ICMR स्टडी में किये गए पेसिमिस्टिक सेनारिओ के अनुसार जहाँ सिम्पटोमैटिक मरीज़ की तरह असिम्पटोमैटिक मरीज़ भी आधे से ज्यादा इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं, ऐसी स्थिति में सिर्फ आधे सिम्पटोमैटिक मरीज़ो को quarantine में रखने का प्रभाव सिर्फ 2 प्रतिशत होगा.

चिंताजनक बात- भारत की मौजूदा स्ट्रेटेजी के अनुसार सिर्फ उन सिम्पटोमैटिक मरीज़ो को चेक करना है जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री है. दिल्ली में पेसिमिस्टिक सेनारिओ के अंतर्गत जहां असिम्पटोमैटिक मरीज़ यह बीमारी फैलाएंगे, अगले 6 महीनों में कम से कम 1.5 मिलियन सिम्पटोमैटिक केसेस होने की संभावना है.

----------x----------x----------x----------

कार्पोरेट

सरकार ने बीएस-IV वाहनों की सीमित बिक्री की अनुमति दी

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एनआईसी को सलाह दी है कि सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 27 मार्च 2020 के निर्देशों के अनुरुप पूरे देश में (दिल्ली/एनसीआर को छोड़कर) बीएस- IV वाहनों के सीमित पंजीकरण के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को अनुपालन सुविधाएं प्रदान करे.

सुप्रीम कोर्ट ने वाहन डीलरों (दिल्ली/एनसीआर को छोड़कर) के पास लंबित बीएस- IV स्टॉक (सुप्रीम कोर्ट को दी गई जानकारी के अनुसार) के सीमित और सशर्त बिक्री की अनुमति दी है, जो कुल स्टॉक के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए. यह कोविड-19 के कारण देश में लगे लॉकडाउन की समाप्ति के 10 दिनों तक वैध होगा.

सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली/एनसीआर में ऐसे वाहनों की बिक्री और पंजीकरण पर रोक बरकरार रखी है. सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 24 अक्टूबर 2018 के आदेशानुसार कोई भी बीएस- IV वाहन 1 अप्रैल 2020 से बेचा या पंजीकृत नहीं किया जाएगा पूरे देश में आज से केवल बीएस- IV वाहनों के पंजीकरण की अनुमति है.

सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के दिए दिशा-निर्देशों में मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय के आदेश का सावधानीपूर्वक अनुपालन करने पर जोर दिया है. सरकार ने भारत चरण (बीएस) उत्सर्जन मानदंड का मानक स्थापित किया है ताकि मोटर वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को विनियमित किया जा सके. बीएस- IV नियम पूरे देश में अप्रैल 2017 से लागू है.

भारत ने 1 अप्रैल से दुनिया के सर्वाधिक स्वच्छ उत्सर्जन मानक अपनाने का फैसला किया है. केवल 3 वर्षों में यूरो-IV से यूरो-IV उत्सर्जन मानकों को अपनाना एक बड़ी उपलब्धि है. दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है.

क्या हैं बीएस वाहन?

बीएस उत्सर्जन मानक वे मानक होते हैं जो भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं. इस उत्सर्जन मानक के जरिये मोटर वाहनों के कारण होने वाले वायु प्रदूषण की मात्रा की व्याख्या की जाती है. बीएस के आगे जितना बड़ा नंबर लिखा होता है उस गाड़ी से उतने ही कम प्रदूषण होने की संभावना होती है. ये बीएस मानक देश का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तय करता है. साथ ही देश में चलने वाली हर गाड़ी के लिए यह आवश्यक होता है कि वह इन सभी मानकों पर खरी उतरे.

पृष्ठभूमि

जस्टिस अरुण मिश्रा और दीपक गुप्ता की एक बेंच ने हाल ही में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले की सुनवाई की. जिसमें स्पष्ट किया कि 1 अप्रैल 2020 से दिल्ली-एनसीआर में कोई भी BS-IV वाहन नहीं बेचा जाएगा. साथ ही यह भी कहा गया कि 24 मार्च से लागू लॉकडाउन खत्म होने के बाद 10 दिनों की अवधि के दौरान बीएस-IV वाहनों की अनसोल्ड इन्वेंट्री की केवल 10 प्रतिशत बिक्री की अनुमति दी जा सकती है. शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि बीएस- IV वाहन जो पहले ही बेचे जा चुके हैं, लेकिन बंद होने के कारण पंजीकृत नहीं हैं, प्रतिबंध हटने के बाद पंजीकृत हो सकते हैं.

भारत में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देंगी ये तीन प्रोत्साहन योजनायें,जानें विस्तार से

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश के इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए लिए तीन प्रोत्साहन योजनाये शुरू करने की अधिसूचना जारी की है. इन योजनाओं के तहत 48,000 करोड़ रुपये से अधिक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी.

ये प्रोत्साहन योजनायें 1 अगस्त, 2020 से लागू होंगी और इन योजनाओं से संबंधित आवेदन शुरु में चार महीने के लिए स्वीकार किये जायेंगे. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने इन योजनाओं को मंजूरी दी थी. इन तीन योजनाओं में उत्पादन से संबंधित

प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) 2.0 और इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों और अर्द्धचालकों (स्पेसस) के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना शामिल है.

उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना

यह तीन योजनाओं में सबसे बढ़ी योजना है जिसके तहत 40,000 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है. इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए 4-6 प्रतिशत का प्रोत्साहन देने के लिए इस राशि का इस्तेमाल किया जायेगा. इन इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में मोबाइल फोन के साथ फोटोपोलिमर फिल्म, मुद्रित सर्किट बोर्ड और असेंबली, परीक्षण, अंकन और पैकेजिंग इकाइयों जैसे इलेक्ट्रॉनिक अवयव शामिल हैं.

उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना की अनिवार्य शर्तें:

- इस योजना के तहत, जो कंपनियां 15000 रुपये या उससे अधिक कीमत के मोबाइल फोन बेचती हैं और जो चार वर्षों में 1,000 करोड़ रुपये का संचयी निवेश करती हैं, उन्हें पहले वर्ष में 250 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलने के साथ ही वे कंपनियां पहले दो साल में 6 प्रतिशत का प्रोत्साहन पाने के लिए योग्य होंगी. उसके बाद अगले दो के लिए 5 प्रतिशत और पांचवें वर्ष में 4 प्रतिशत प्रोत्साहन उन कंपनियों को दिया जायेगा.
- पहले वर्ष इन कंपनियों के निर्मित माल की वृद्धिशील बिक्री 4,000 करोड़ रुपये होनी चाहिए और पांचवें वर्ष तक कुल बिक्री लगभग 25,000 करोड़ रुपये होगी.
- घरेलू मोबाइल फोन कंपनियों के लिए चार वर्षों में निवेश सीमा 200 करोड़ रुपये है और पांच वर्षों में बिक्री मानदंड 5,000 करोड़ रुपये है.
- अगले 4 साल के लिए घटकों के लिए निवेश की सीमा 100 करोड़ रुपये और अगले 5 साल में 600 करोड़ रुपये की बिक्री निर्धारित की गई है.
- इस योजना के तहत प्रोत्साहन 01 अगस्त से लागू होगा और शुरु में आवेदन चार महीने के लिए स्वीकार किये जायेंगे.

दो अन्य अधिसूचित योजनाओं में शामिल हैं:

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) 2.0

इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों और अर्द्धचालकों (स्पेसस) के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना.

महत्व

सरकार की इन तीनों प्रोत्साहन योजनाओं में 48,042.25 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 20 लाख करोड़ रुपये का निवेश होने की संभावना जताई गई है और इससे अगले 5-6 वर्षों में लगभग 25 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे. यह उम्मीद है कि वर्ष 2025 तक भारत को 01 खराब डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में ये तीनों योजनायें बड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी.

---------X----------x----------x------

अर्थव्यवस्था

विश्व में आर्थिक मंदी की गुंजाइश,बच सकते हैं भारत और चीन: संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र ने अपनी नवीनतम व्यापार रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह बताया गया है कि विश्व की अर्थव्यवस्था इस बार मंदी के दौर से गुजरेगी. कोरोना वायरस महामारी के कारण, विश्व की आय में अरबों डॉलर का नुकसान होगा.

यह स्थिति विकासशील देशों के लिए गंभीर संकट पैदा करेगी लेकिन व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत और चीन पर इस वैश्विक आर्थिक मंदी का कोई खास असर नहीं पड़ेगा. संयुक्त राष्ट्र ने विकासशील देशों को सहायता प्रदान करने के लिए 2.5 ख़रब अमरीकी डॉलर के पैकेज की घोषणा की है और इन देशों में विश्व की जनसंख्या का लगभग एक तिहाई हिस्सा रहता है.

कोविड -19 महामारी के कारण जिस तीव्र गति से विकासशील देशों में आर्थिक मादी आई है, वह वर्ष 2008 के वैश्विक वित्त संकट की तुलना में कहीं अधिक गंभीर है.

भारत और चीन पर वैश्विक आर्थिक मंदी का असर

UNCTAD की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इस साल विश्व में आर्थिक मंदी का संकट आ सकता है जिसमें ख़रबों डॉलर का नुकसान हो जायेगा और इसका काफी गंभीर असर विकासशील देशों पर पड़ेगा. लेकिन भारत और चीन पर इसका काफी कम असर पड़ने की संभावना इस रिपोर्ट में जताई गई है. हालांकि, इस रिपोर्ट में भारत और चीन के इस आर्थिक मंदी से बच जाने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है.

अर्थव्यवस्था

विश्व में आर्थिक मंदी की गुंजाइश,बच सकते हैं भारत और चीन: संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र ने अपनी नवीनतम व्यापार रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह बताया गया है कि विश्व की अर्थव्यवस्था इस बार मंदी के दौर से गुजरेगी. कोरोना वायरस महामारी के कारण, विश्व की आय में अरबों डॉलर का नुकसान होगा.

यह स्थिति विकासशील देशों के लिए गंभीर संकट पैदा करेगी लेकिन व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत और चीन पर इस वैश्विक आर्थिक मंदी का कोई खास असर नहीं पड़ेगा. संयुक्त राष्ट्र ने विकासशील देशों को सहायता प्रदान करने के लिए 2.5 ख़रब अमरीकी डॉलर के पैकेज की घोषणा की है और इन देशों में विश्व की जनसंख्या का लगभग एक तिहाई हिस्सा रहता है.

कोविड -19 महामारी के कारण जिस तीव्र गति से विकासशील देशों में आर्थिक मादी आई है, वह वर्ष 2008 के वैश्विक वित्त संकट की तुलना में कहीं अधिक गंभीर है.

भारत और चीन पर वैश्विक आर्थिक मंदी का असर

UNCTAD की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इस साल विश्व में आर्थिक मंदी का संकट आ सकता है जिसमें ख़रबों डॉलर का नुकसान हो जायेगा और इसका काफी गंभीर असर विकासशील देशों पर पड़ेगा. लेकिन भारत और चीन पर इसका काफी कम असर पड़ने की संभावना इस रिपोर्ट में जताई गई है. हालांकि, इस रिपोर्ट में भारत और चीन के इस आर्थिक मंदी से बच जाने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है.

विकासशील देशों का UNCTAD विश्लेषण

'विकासशील देशों को कोविड – 19 झटका' शीर्षक के विश्लेषण के अनुसार, विश्व जनसंख्या के दो-तिहाई पीछे छूटने वाले लोगों के लिए 'व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) के द्वारा आयोजित जो भी यह लेता है' कार्यक्रम में, संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास निकाय ने यह बताया है कि, आने वाले दो वर्षों में ज्यादा निर्यात करने वाले देशों के विदेशी निवेश में 2 खरब से 3 खरब अमरीकी डॉलर तक की गिरावट आयेगी.

UNCTAD की वैश्विक आर्थिक मंदी की व्याख्या

- जी-20 में चीन और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के एक-साथ विशाल सरकारी पैकेजेज के कारण, इन देशों की अर्थव्यवस्था को जीवंत बनाये रखने के लिए 5 खरब अमरीकी डॉलर पैकेज की सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है.
- इस पैकेज के साथ, UNCTAD ने 1 खरब से 2 खरब अमरीकी डॉलर की मांग का अनुमान लगाया है जो प्रमुख जी-20 अर्थव्यवस्थाओं को प्रदान की जायेगी.
- UNCTAD के एक अन्य अनुमान के अनुसार, विकासशील देशों को 2 खरब से 3 खरब अमरीकी डॉलर तक वित्तीय नुकसान होगा.
- इस महामारी के कारण उत्पन्न वैश्विक संकट और आर्थिक मंदी का मुकाबला करने के लिए राजकोषीय, प्रशासनिक और मौद्रिक क्षमता की कमी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए विनाशकारी साबित होगी.

विश्व आर्थिक मंदी से बचने के लिए UNCTAD के महत्त्वपूर्ण सुझाव

- जिन देशों पर इस महामारी का विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है, उन देशों को 1 खरब अमरीकी डॉलर नकदी की सहायता प्रदान की जायेगी. यह काम आईएमएफ में मौजूदा विशेष आहरण अधिकार को पुन: आवंटन करके किया जा सकता है.
- संकटग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं की मदद के लिए, एक ऋण जयंती जिसके तहत विकासशील देशों का 1 खरब डॉलर का ऋण इस वर्ष के लिए रद्द किया जाना चाहिए.

- स्वास्थ्य सुधार के लिए 500 अरब डॉलर का मार्शल प्लान, जिसके लिए कुछ समय पहले वादा किया गया था, लेकिन इसके तहत रकम नहीं दी गई थी, उसके लिए गैर-जारी आधिकारिक विकास सहायता (ODA) से वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी.

विश्व बैंक ने भारत को कोविड-19 परियोजना के लिए 01 अरब डॉलर देने की पेशकश की

विश्व बैंक ने भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणालियों की तैयारी से संबंधित परियोजना के लिए 01 अरब डॉलर देने की पेशकश की है. विश्व बैंक अपनी कोविड-19 शीघ्र निपटान सुविधा के माध्यम से यह कोष आवंटित करेगा.

इस चार वर्ष की परियोजना का उद्देश्य कोविड – 19 महामारी के दौरान भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को विकसित करना है. यह परियोजना दीर्घकालिक नीतियों के निर्माण में मदद करेगी जोकि इस महामारी का अलग स्तर आने पर मदद करेगी.

इस परियोजना का पूरा ध्यान भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के साथ कोविड-19 के खतरे को कम करने पर केंद्रित होगा. इस प्रस्तावित कोष के माध्यम से, विश्व बैंक और भारत सरकार सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं का पालन करके कोविड-19 महामारी से जुड़े खतरे से बचने के लिए प्रत्येक संभव प्रयास करेंगे.

भारत की कोविड-19 परियोजना की मुख्य विशेषताएं:

- इस परियोजना का एक लक्ष्य आने वाले वर्षों में स्वास्थ्य संबंधी किसी भी संकट से निपटने के लिए पूर्व-तैयारी में भारत की सहायता करना है.

- इस परियोजना की प्रगति को कुछ मुख्य संकेतकों के आधार पर मापा जाएगा जैसेकि SARS-COV-2 प्रयोगशाला परीक्षण के लिए प्रस्तुत नमूना अनुपात, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा निर्धारित मानक समय-सीमा के भीतर पुष्टि प्रदान की गई है.
- एक अन्य प्रमुख संकेतक कोविड-19 प्रयोगशाला से पुष्टि-प्राप्त ऐसे मामलों का अनुपात होगा जिन पर 48 घंटे के भीतर प्रतिक्रिया दी जायेगी.
- इस परियोजना का एक मुख्य उद्देश्य कोविड-19 के खतरे से समुचित तरीके से निपटने के साथ-साथ भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना भी है.

भारत की कोविड-19 परियोजना का महत्व:

भारत और विश्व बैंक के बीच इस साझेदारी का उद्देश्य इस महामारी के प्रति भारत की आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को सुदृढ़ करना है. कोविड – 19 महामारी को रोकने की क्षमता को बढ़ाने के लिए इस परियोजना के तहत भारत को तत्काल सहायता प्रदान की जायेगी.

यह उद्देश्य उन्नत निगरानी क्षमताओं, स्वास्थ्य जांच आदि के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, इससे भारत में कोविड-19 महामारी फ़ैलने का खतरा भी कम और फिर धीरे-धीरे समाप्त हो जायेगा.

महिलाओं के जनधन खाते में पहली किस्त जमा, जानें विस्तार से

मोदी सरकार ने कोरोना संकट के कारण से गरीबों के बैंक खातों में पैसे डालने का घोषणा किया था. देशभर में लॉकडाउन की घोषणा के बाद सरकार गरीब महिलाओं के जनधन खाते में हर महीने 500 रुपये डालेगी. सरकार की तरफ यह मदद की रकम तीन महीने तक दी जाएगी.

देश में 20 करोड़ से भी ज्यादा जन-धन खाताधारक महिलाओं के लिए भी मोदी सरकार ने बड़ी घोषणा की है. लोगों से कहा गया है कि वह यह राशि अपनी सुविधानुसार बाद में कभी भी निकाल सकते हैं. सरकार द्वारा निकासी के लिए एटीएम का प्रयोग करने की सलाह दी गई है.

प्रधानमंत्री जनधन योजना

सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जीरो बैलेंस पर बचत खाते खोले गए हैं. इन खातों में ही यह राशि प्रदान की जाएगी. जनधन खाता खुलवाने पर दुर्घटना बीमा, ओवरड्राफ्ट फेसिलिटी और चेकबुक सहित अन्य लाभ भी मिलते हैं.

जनधन खातों में डाले जाएंगे पैसे

इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) ने सभी बैंकों को आदेश दिया है कि वह अपने यहां महिलाओं के जनधन खाते में 3 अप्रैल से 500 रुपये हर महीने डालना शुरु कर दें.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार महिलाओं के जनधन खाते में तीन महीने तक हर महीने 500 रुपये की राशि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मदद में दी जाएगी. खाताधारकों के अकाउंट में पैसे उनके अकाउंट नंबर के आखिरी अंक के अनुसार अलग-अलग दिन डाले जाएंगे, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो.

पैसे डालने का नियम

इंडियन बैंक एसोसिएशन के अनुसार, जिन जनधन खातों की आखिरी डिजिट 0 या 1 है, उस खाते में 3 अप्रैल को पैसे डाले गए. जनधन खातों की आखिरी डिजिट 2 या 3 है, उस खाते में 4 अप्रैल को पैसे डाले गए. जिन जनधन खातों की आखिरी डिजिट 4 या 5 है, उस खाते में 7 अप्रैल को पैसे डाले गए. जिन जनधन खातों की आखिरी डिजिट 6 या 7 है, उस खाते में 8 अप्रैल को पैसे डाले गए. हालांकि, जिन जनधन खातों की आखिरी डिजिट 8 या 9 है, उस खाते में 9 अप्रैल को पैसे डाले गए है.

पृष्ठभूमि

गौरतलब है कि देश में लॉकडाउन के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि गरीब महिलाओं के जनधन खातों में हर महीने 500 रुपये डाले जाएंगे. कुल जनधन खातों में 53 प्रतिशत महिलाओं के नाम है. इस तरह से लगभग 20 करोड़ महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा. सरकार के

बयान के अनुसार किसी भी बैंक के एटीएम से पैसा निकाला जा सकता है और सरकार के निर्देश के अनुसार उसके लिये फिलहाल कोई शुल्क नहीं देना होगा.

इसके अतिरिक्त बैंकों को पीएम-किसान योजना के लाभार्थियों को भी देखना है. इसके तहत पहली किस्त के रुप में 2,000 रुपये दी जा रही है. इस योजना में सालाना तीन किस्तों में 6,000 रुपये दी जाती है. बैंकों को अगले तीन महने महीने में तीन करोड़ गरीब विधवा पेंशनभोगियों और गरीब दिव्यांगों के खाते में 1,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने को कहा गया है.

सरकार ने EPFO खाताधारकों को दी बड़ी राहत, अब आधार भी होगा डेट ऑफ बर्थ की पहचान

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के बीच ईपीएफओ रिकॉर्ड में जन्म की तिथि को सुधारने के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं. ईपीएफओ खाते के केवाईसी (Know your customer) के अनुपालन को सुनिश्चित करने को लेकर अपने अंशधारकों की जन्म तिथि में सुधार हेतु आधार कार्ड को वैध साक्ष्य मानेगा तथा उसे ऑनलाइन स्वीकार करेगा.

ईपीएफओ ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर ऑनलाइन सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच बढ़ाने हेतु अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी करके पीएफ सदस्यों को ईपीएफओ रिकॉर्ड्स में उनकी जन्मतिथि को सुधारने की सुविधा प्रदान की है. इसके तहत पीएफ सदस्य ईपीएफओ रिकार्ड में अपनी जन्म तिथि आसानी से सुधार सकेंगे.

श्रम मंत्रालय ने 05 अप्रैल 2020 को एक बयान में कहा कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए ऑनलाइन सेवाओं की पहुंच और उपलब्धता बढ़ाने हेतु ईपीएफओ ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को संशोधित निर्देश जारी किया है. आधार में दर्ज जन्म तिथि को अब सुधार के उद्देश्य से जन्मतिथि के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा.

मुख्य बिंदु

- नए निर्देश के मुताबिक, आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि को भी अब जन्मतिथि के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा.
- इसके अंतर्गत पीएफ सदस्य ईपीएफओ रिकार्ड में अपनी जन्म तिथि आसानी से सुधार सकेंगे. इससे यह सुनिश्चित होगा कि यूएएन (सार्वभौमिक खाता संख्या) केवाईसी का अनुपालन करती है.
- बयान के मुताबिक, आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि को अब सुधार के लिए वैध साक्ष्य मना जाएगा. हालांकि, दोनों जन्मतिथि में तीन साल से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए.
- पीएफ अंशधारक सुधार हेतु अनुरोध ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. इससे ईपीएफपीओ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के साथ तत्काल ऑनलाइन जन्म तिथि का सत्यापन कर सकेगा. इससे अनुरोध को अमल में लाने में लगने वाला समय कम होगा.
- ईपीएफओ ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों से कहा है कि वे ऑनलाइन अनुरोध का तेजी से निपटान करें. इससे कोरोना वायरस महमारी और 'लॉकडाउन' के कारण आर्थिक संकट में फंसे भविष्य निधि सदस्यों को अपने खाते से पैसा निकालने को लेकर ऑनलाइन आवेदन में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा.

पृष्ठभूमि

ईपीएफओ ने इससे पहले अपने अंशधारकों को अपने अपने वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) को खाते से निकालने की अनुमति दी थी. कोरोना वायरस और देशव्यापी बंद को देखते हुए खाते से ऑनलाइन आवेदन देकर राशि निकालने की अनुमति दी गई. हालांकि, यह सुविधा उन्हीं अंशधारकों के लिए उपलब्ध है, जिनका खाता केवाईसी नियमों का पालन करता है. इस निर्णय से अंशधारकों को अपना सावैभौमिक खाता संख्या केवाईसी नियमों के अनुरूप करने में सहायता मिलेगी.

भारत की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2020-21 में 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान : UN रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र के 'एशिया और प्रशांत आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण (ESCAP)' वर्ष 2020 की ओर से स्थायी अर्थव्यवस्थाओं के लिए जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) 4.8 फ़ीसदी रहने का अनुमान है. यह भविष्यवाणी 10 मार्च, 2020 तक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई थी.

वर्ष 2019-20 के लिए भारत की जीडीपी 5 फ़ीसदी रहने का अनुमान लगाया गया था और विकास दर में वर्ष 2020-21 में 4.8 तक गिरावट का अनुमान है. इस रिपोर्ट में वर्ष 2021-22 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 5.1 फ़ीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है.

पिछले कुछ महीनों में भारत की जीडीपी में काफी गिरावट आई है, इसकी वजह रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और एविएशन सेक्टर में मांग कम होना और क्रेडिट लिमिट का कम होना है. भारत की जीडीपी जुलाई-सितंबर 2019 की तिमाही में अपने पिछले 7 वर्षों में सबसे कम 4.5 फ़ीसदी थी. आय में कमी और बढ़ती बेरोजगारी ने भी भारत में विकास दर को धीमा किया है.

आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में अनुमानित वृद्धि

केंद्रीय बजट 2020-21 से एक दिन पहले पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद 6-6.5 फ़ीसदी तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया है जोकि वर्ष 2019-20 में 5 फ़ीसदी था.

एशिया और प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर कोविड -19 महामारी का प्रभाव

- UN ESCAP रिपोर्ट 2020 में कहा गया है कि कोविड -19 महामारी के प्रकोप की वजह से अन्य देशों के साथ होने वाले पर्यटन, व्यापार और अन्य वित्तीय क्रियाकलापों में कमी के कारण एशिया और प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है.

- 31 मार्च, 2020 तक कोविड – 19 के मामले लगातार बढ़ने के साथ ही नोवल कोरोनो वायरस महामारी पूरी दुनिया में तेजी से फैल रही है. कोविड-19 महामारी सबसे पहले चीन के वुहान शहर में बड़ी तेजी से फ़ैली और जल्दी ही पूरी दुनिया के कई देशों में फैल गई.
- कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कई उपाय जैसेकि लॉकडाउन, क्वारंटाइन और अन्य कई उपाय अपनाये जाने के बावजूद, इस महामारी ने पहले ही एशिया और प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं के साथ विश्व की अधिकतर अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है.
- कोविड-19 के परिणामस्वरुप, UN ESCAP रिपोर्ट के अनुसार, व्यापारिक गतिविधियों में कमी के कारण एशिया-प्रशांत क्षेत्र की जीडीपी में 0.6-0.8 फ़ीसदी तक की गिरावट आ सकती है.

विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर

वर्ष 2008 की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 में, विश्व अर्थव्यवस्था 2.3 फ़ीसदी की धीमी गति से बढ़ी, जबकि वर्ष 2018 में यह जीडीपी 3 फ़ीसदी थी. वर्ष 2020 में विश्व अर्थव्यवस्था के 2020-21 में 2.0 फ़ीसदी की वृद्धि के साथ धीमा होने की उम्मीद है.

इसके अलावा, एशिया-प्रशांत क्षेत्र की विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मंदी को भारत, चीन और रूस जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने और अधिक बढ़ाया है.

UN ESCAP रिपोर्ट में सुझाए गए समाधान

विश्व अर्थव्यवस्था पर कोविड -19 के प्रभाव को दूर करने के लिए, एशिया-प्रशांत क्षेत्र के सभी देशों सहित विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और आपस में समन्वय और सहयोग को मजबूत करना चाहिए.

G-20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक: ऊर्जा की खपत का प्रमुख केंद्र बना रहेगा भारत

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 10 अप्रैल 2020 को G-20 असाधारण ऊर्जा मंत्रियों की आभासी बैठक में भाग लिया. भारत, अमेरिका को हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन दवाओं की सप्लाई करने के बाद ऊर्जा के क्षेत्र में भी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने को तैयार है. इस बैठक को सऊदी अरब द्वारा बुलाया गया था, और इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ऊर्जा मंत्री द्वारा की गई थी.

जी-20 देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिरकत की. इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत इस वैश्विक संकट के दौरान भी ऊर्जा की खपत का प्रमुख केंद्र बना रहेगा. इस बैठक में मांग में कमी और उत्पादन अधिशेष के बीच स्थिर ऊर्जा बाजारों को सुनिश्चित करने के तरीकों और साधनों पर चर्चा की गई.

जी-20 समूह के ऊर्जा मंत्रियों की ओर से 11 अप्रैल 2020 को एक संयुक्त वक्तव्य जारी कर यह जानकारी दी गयी. संयुक्त वक्तव्य के मुताबिक जी-20 देशों के ऊर्जा मंत्रियों ने महामारी कोविड-19 की

वैश्विक चुनौती के बीच अंतरराष्ट्रीय तेल एवं ऊर्जा बाजार की स्थिरता को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने को लेकर प्रतिबद्धता जताई है.

जी-20 देशों के अलावा कई संगठन भी हुए शामिल

कोरोना संकट के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जी-20 देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष देश के रुप में सऊदी अरब ने की. सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज़ के साथ जी-20 के सभी देशों के ऊर्जा मंत्री इस बैठक में विशेष रुप से मौजूद रहे. जबकि ऊर्जा के साथ तेल एवं गैस क्षेत्र से जुड़े अंतरराष्ट्रीय संगठन ओपेक, आईईए (इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन) और इंटरनेशनल एनर्जी फोरम (आईईएफ) विशेष रुप से आमंत्रित थे.

उज्ज्वला गैस की नि:शुल्क आपूर्ति

कोरोना संकट को लेकर विश्वभर में जताई जा रही आशंकाओं के बीच ऊर्जा क्षेत्र में मांग कम रहने की आशंका बड़ी-बड़ी आर्थिक महाशक्तियों को सता रही है. इस मौके पर इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने covid-19 से निपटने को लेकर जी-20 देशों की मानवीय पहल की प्रशंसा कर चुके हैं. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में 8 करोड़ से अधिक लोगों को उज्ज्वला गैस की नि:शुल्क आपूर्ति की जा रही है. 1.7 लाख करोड़ से अधिक के राहत पैकेज के अंतर्गत उठाए गए इस कदम से जहां ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा के साथ सामाजिक सशक्तिकरण को बल मिलेगा. वहीं ग्लोबल एनर्जी डिमांड को भारत से रफ्तार मिलेगी.

इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा की मांग को गति देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से और भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं. प्रधान ने तेल बाजार में आ रहे उतार-चढ़ाव पर कहा कि भारत हमेशा तेल बाजार में स्थिरता का पैरोकार रहा है, जिससे कि न सिर्फ उत्पादकों बल्कि उपभोक्ताओं के हितों की भी रक्षा हो. उन्होंने इस मौके पर तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और ओपेक प्लस देशों द्वारा तेल की आपूर्ति को लेकर उठाए गए प्रभावी कदमों की भी प्रशंसा की.

जी-20 देश की अगली बैठक

बयान में यह भी कहा गया कि तेल बाजार की स्थिति पर जी-20 देश अगली बैठक सितंबर में करेंगे. लेकिन यदि जरूरी हुआ तो सितंबर से पहले भी बैठक हो सकती है. साथ ही सदस्यों ने सिर्फ तेल

बाजार की स्थिरता के लिए प्रतिबद्धता जताई. इससे पहले 09 अप्रैल 2020 को ओपेक प्लस बैठक में रिकॉर्ड उत्पादन कटौती के लिए बनी योजना पर अकेले मेक्सिको असहमत था.

कोविड-19 के कारण विश्वभर में कच्चे तेल की मांग और आपूर्ति में असाधारण कमी आई है जिससे ऊर्जा बाजार में काफी अस्थिरता देखी जा रही है। इसके कारण कई देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है. लाखों लोगों के रोजगार पर खतरा मंडरा रहा है.

एडीबी भारत को कोरोना वायरस से लड़ने हेतु 16,700 करोड़ रुपये की मदद देगा

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने हाल ही में भारत को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में लगभग 16,700 करोड़ रुपये की मदद देने की घोषणा की है. एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मासत्सुगु असाकावा ने कहा कि भारत की आपातकालीन ज़रूरत पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. विश्व बैंक ने इससे पहले भारत को कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ 7,600 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है.

गौरतलब है कि भारत में 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है. मासत्सुगु असाकावा ने कहा कि एडीबी भारत की आपातकालीन जरूरतों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है. हम अब स्वास्थ्य क्षेत्र में तत्काल सहायता के लिए 2.2 अरब अमेरिकी डॉलर की तैयारी कर रहे हैं. इससे गरीबों पर महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने में सहायता मिलेगी.

सरकार ने तीन सप्ताह के देशव्यापी लॉकडाउन से प्रभावित गरीबों, महिलाओं और श्रमिकों को तत्काल नकद और राशन जैसी सहायता मुहैया कराने हेतु इस राहत पैकेज की घोषणा की है. एडीबी ने एक बयान में कहा कि इस दौरान वह निजी क्षेत्र की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए भी काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर भारत के लिए एडीबी की सहायता को और बढ़ाया जाएगा.

पृष्ठभूमि

गौरतलब है कि भारत में कोरोना वायरस के केसों में लगातार बढ़ रहे हैं और इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है. देश के सभी राज्यों से इसके मरीज सामने आ रहे हैं.

हेलिकॉप्टर मनी: कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को COVID-19 संकट से बचायेगा

कोरोना वायरस को लेकर जारी लॉकडाउन 14 अप्रैल 2020 को खत्म हो रहा है. कई राज्य के मुख्यमंत्री इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. ओडिशा, पंजाब और तेलंगाना ने तो लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया. इसमें कोई शक नहीं है कि आर्थिक गतिविधि ठप होने के कारण देश को भारी नुकसान हो रहा है जिसके लिए हर सेक्टर से वित्तीय पैकेज की मांग की जा रही है.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन कोरोना वायरस महामारी के कारण पैदा होने वाले आर्थिक संकट से निपटने में मदद करने की इच्छा जताई है.

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने आरबीआई को सुझाव दिया है कि वह राज्य सरकारों को मौजूदा संकट से निपटने में मदद करने के लिए हेलीकाप्टर मनी की अवधारणा को अपनाए और भारत में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा दे.

पूरे विश्व में इन दिनों हेलिकॉप्टर मनी की चर्चा हो रही है. ऐसे में यह क्या होता है इसे समझने की कोशिश करते हैं. हेलिकॉप्टर मनी शब्द नियमित रूप से खबरों में आता रहा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका क्या मतलब है. हेलीकॉप्टर मनी क्या है और यह वर्तमान COVID-19 महामारी को प्रबंधित करने में कैसे मदद कर सकता है.

हेलिकॉप्टर मनी क्या है?

गहराते आर्थिक संकट के बीच जब लोगों को इस उम्मीद से फ्री में पैसे बांटे जाते हैं कि इससे उनका ख़र्च और उपभोग बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था सुधरेगी. यही 'हेलिकॉप्टर मनी' है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हेलिकॉप्टर मनी का पहली बार प्रयोग साल 1969 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने किया था. अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इसका अर्थ अपरंपरागत तौर पर आर्थिक नीति में बड़ा बदलाव करना और बड़े पैमाने पर नोटों को छापना और उसे ग्रोथ हेतु बाजार में लगाना है.

हेलिकॉप्टर मनी के तहत देश का सेंट्रल बैंक पहले बड़े पैमाने पर नोटों की छपाई करता है और सरकार को दे देता है. इस प्रोग्राम के तहत सरकार को यह पैसा सेंट्रल बैंक को रिफंड नहीं करना पड़ता है. जब अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो जाती है तो सरकार सेंट्रल बैंक की सहायता से मनी सप्लाई बढ़ा देती है जिससे मांग और महंगाई में तेजी आती है.

हेलिकॉप्टर मनी से भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे मदद मिलेगी?

हेलीकॉप्टर मनी का व्यावहारिक क्रियान्वयन बहुत सावधानी की मांग करता है. इसके माध्यम से देश की सरकार अपने आसमानी आर्थिक संकट के दौरान देश के लोगों को इस आशा के साथ फ्री में पैसे बांटती है कि इससे उनका ख़र्च और उपभोग दोनो ही बढ़ेंगे जिसके माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी. हेलिकॉप्टर मनी का सीधा प्रभाव लोगों की डिस्पोजेबल आय में वृद्धि, अर्थव्यवस्था में मांग और मुद्रास्फीति को बढ़ावा देने के इरादे से धन की आपूर्ति में वृद्धि है.

तेलंगाना के सीएम ने सुझाव दिया था

हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने सुझाव देते कहा था कि आर्थिक संकट का मुकाबला करने के लिए हमें एक रणनीतिक आर्थिक नीति की आवश्यकता है. आरबीआई को सहजता की नीति लागू करनी चाहिए. इससे राज्यों और वित्तीय संस्थानों को धन अर्जित करने में सुविधा होगी। हम वित्तीय संकट से बाहर आ सकते हैं.

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार से मांग की कि वे फिस्कल डेफिसिट का टार्गेट GDP के तीन फीसदी के मुकाबले पांच फीसदी रखे. इसके अलावा क्वांटिटेटिव ईजिंग के जरिए GDP का पांच फीसदी जारी करने को कहा है. हेलीकॉप्टर मनी आसमानी आर्थिक संकट का समाधान है जो कि

महामारी जैसी असाधारण आपदा के दौर में लोगों को बचाने के लिए सरकार की तरफ़ से उन्हें वित्तीय सहायता देने जैसी प्रक्रिया है.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के करोड़ों लाभार्थियों के खातों में 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि जमा

अब तक तेल विपणन कंपनियों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत एलपीजी सिलेंडर की मुफ्त वितरण का लाभ उठाने वाले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के 7.15 करोड़ लाभार्थियों के खातों में 5,560 करोड़ रुपये की राशि जमा करवाई है. इस महीने लाभार्थियों ने 1.26 करोड़ सिलेंडरों की बुकिंग करवाई थी, जिसमें से लगभग 85 लाख सिलेंडर पीएमयूवाई लाभार्थियों को वितरित किए गए हैं.

इस समय देश में 27.87 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता हैं, जिनमें से 8 करोड़ से अधिक पीएमयूवाई लाभार्थी हैं. लॉकडाउन शुरु होने के बाद से, देश में प्रतिदिन 50 से 60 लाख सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं. ऐसे समय में, जब देशव्यापी लॉकडाउन जारी है और लोग सुरक्षित रहने के लिए अपने घर के भीतर ही रहते हैं, तो एलपीजी वितरण करने वाले लोग और एलपीजी की आपूर्ति करने वाले अन्य सभी कर्मचारी स्वच्छ ईंधन सीधे सभी लोगों के घर तक पहुंचाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं.

केंद्र सरकार ने कोविड -19 के खिलाफ़ आर्थिक प्रतिक्रिया के एक हिस्से के तौर पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब सहायता पहल की घोषणा की है. इस योजना के अनुसार, उज्ज्वला लाभार्थियों को अप्रैल से जून तक की पूरे 3 महीने की अवधि में मुफ्त एलपीजी सिलिंडर प्रदान किए जाने हैं.

पर्वतीय इलाकों से लेकर समुद्र के किनारे बसे लोगों के घरों तक, रेगिस्तानों में बसे लोगों से लेकर जंगलों में बसे लोगों के घरों तक ये कोरोना योद्धा अपने कर्तव्यों में दृढ़ हैं और समय पर एलपीजी सिलिंडरों का वितरण कर रहे हैं. यहां तक कि इस संकटपूर्ण समय में भी, अधिकांश स्थानों पर सिलेंडर की प्रतीक्षा अवधि 2 दिन से कम है.

इस 31 मार्च तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन रखने वाले सभी ग्राहक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ पाने के लिए पात्र हैं. यह योजना 1 अप्रैल से शुरु हुई है और यह 30 जून तक जारी रहेगी.

विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021 में भारत के धीमे आर्थिक विकास का अनुमान लगाया

विश्व बैंक ने अपनी दक्षिण एशिया आर्थिक फ़ोकस रिपोर्ट में यह कहा है कि वर्ष 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद से भारत में इस वित्त वर्ष 2021 में सबसे धीमा आर्थिक विकास होगा. भारत में यह धीमी आर्थिक विकास दर कोरोना वायरस महामारी के परिणामस्वरुप होगी जिससे भारत की अर्थव्यवस्था गंभीर रुप से प्रभावित हुई है.

विश्व बैंक की इस रिपोर्ट के अनुसार, इस कोविड - 19 महामारी का प्रकोप ऐसे समय पर हुआ जब भारत की अर्थव्यवस्था में पहले से ही वित्तीय क्षेत्र की कमजोरियों के कारण धीमी गति से विकास हो रहा था. भारत द्वारा कोरोना वायरस के खिलाफ बरती जाने वाली सावधानियों के परिणामस्वरुप भी वित्त वर्ष 2021 में विकास में तेज़ी से कमी आयेगी.

विश्व बैंक ने यह भी कहा है कि भारत में लंबे समय तक लॉकडाउन जारी रहने के कारण आर्थिक परिणाम पूर्व-अनुमानों से कहीं अधिक गंभीर/ ख़राब हो सकते हैं.

विश्व बैंक की रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:

- विश्व बैंक के अनुसार, वित्त जो 1 अप्रैल से शुरु हुए वर्ष 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था 1.5 प्रतिशत से 2.8 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है. 30 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष 2019-20 में भारत के लिए पूर्व अनुमानित विकास दर 4.8 प्रतिशत से 5 प्रतिशत थी.

- भारत सरकार के इस लॉकडाउन के दौरान उड़ानों के निलंबन, कारखानों और व्यवसायों को बंद करने के साथ ही लोगों और वस्तुओं की आवा-जाही को प्रतिबंधित किया गया है जिससे देश का सेवा क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित होगा.
- विश्व बैंक के अनुसार, वित्त वर्ष 2022 में कोविड - 19 के प्रभाव में कमी आने के कारण भारत का आर्थिक विकास 5% तक बढ़ने की उम्मीद है.
- अपनी इस रिपोर्ट में, विश्व बैंक ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया है, जिसमें मुख्य रूप से आठ देश शामिल थे. इस साल 1.8 प्रतिशत से 2.8 प्रतिशत तक वृद्धि का अनुमान लगाया है. यह अनुमान छह महीने पहले लगाये गए अनुमान 6.3 प्रतिशत से काफ़ी कम है.
- विश्व बैंक की इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 1 प्रतिशत से कुछ अधिक राशि को उन सभी कार्यक्रमों के लिए अलग कर दिया है, जिनके तहत बेरोजगारों को मुआवजा देने के साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र के खर्च, मुफ्त भोजन, ब्याज मुक्त ऋण, और नकदी के अंतरण की व्यवस्था भी की जायेगी.

अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा भारत के आर्थिक विकास का अनुमान:

- एशियाई विकास बैंक ने भारत की आर्थिक विकास दर को चालू वित्त वर्ष में 4 प्रतिशत तक कम करके आंका है.
- स्टैंडर्ड एंड पूअर्स ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत के जीडीपी के पूर्वानुमान को 5.2 प्रतिशत से 3.5 प्रतिशत तक कम कर दिया है.
- फिच रेटिंग ने भारत की अनुमानित वृद्धि 2 प्रतिशत दर्शाई है.
- इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अनुमान लगाया है कि भारत की वृद्धि दर पूर्व अनुमान 5.5 प्रतिशत से कम होकर 3.6 प्रतिशत तक रहेगी.
- मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने भारत की अनुमानित विकास दर 5.3 प्रतिशत के पूर्व अनुमान से घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दी है.

तेल उत्पादन पर हुआ बड़ा समझौता, ऊर्जा क्षेत्र में हजारों नौकरियां बचेंगी

तेल उत्पादक देशों के संगठन 'ओपेक' और रूस के नेतृत्व वाले उसके तेल उत्पादक सहयोगियों के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है. इस समझौते के बाद कोरोना वायरस के संक्रमण से अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल की मांगों में आई कमी के कारण क़ीमत को स्थिर रखने के लिए उत्पादन में 10 प्रतिशत की कटौती होगी. यह समझौता अगले महीने एक मई से प्रभावी होगा.

इस समझौते के तहत वे कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण मांग में आई कमी के मद्देनज़र उत्पादन में प्रतिदिन 97 लाख बैरल की कटौती करने पर राज़ी हुए हैं. यह एक बार में की गई इतिहास में सबसे बड़ी कटौती है. 12 अप्रैल 2020 को इस समझौते पर एक वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिए सहमति बनी. समझौते का मुख्य उद्देश्य क़ीमत को स्थिर रखने के लिए उत्पादन में बड़ी कटौती करनी थी.

09 अप्रैल को समझौता होना था

ओपेक प्लस तेल उत्पादकों के बीच 09 अप्रैल 2020 को कटौती को लेकर समझौता होना था लेकिन मेक्सिको उत्पादन में कटौती का विरोध कर रहा था. ओपेक ने इस समझौते की घोषणा नहीं की

है लेकिन इससे जुड़े कई देशों ने समझौते की पुष्टि की है. अब तक इस बात की पुष्टि हुई है कि ओपेक और सहयोगी तेल उत्पादक देश हर दिन 90.7 लाख बैरल की कटौती तेल उत्पादन में करेंगे. इस समझौते की जानकारी अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कुवैत के ऊर्जा मंत्री डॉ ख़ालीद अली मोहम्मद अल-फ़ादेल ने ट्वीट कर दी है.

तेल की मांग में एक तिहाई की कमी

विश्वभर में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण तीन अरब आबादी घरों में बंद है और इस वजह से तेल की मांग में एक तिहाई की कमी आई है.

ओपेक प्लस इस उत्पादन में कटौती को लेकर तैयार नहीं था इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल की क़ीमत पिछले 18 साल बाद सबसे निचले स्तर पर आ गई थी. पहले सऊदी अरब और रूस में मतभेद के कारण कटौती पर कोई समझौता नहीं बन पा रहा था. अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 02 अप्रैल 2020 को सऊदी और रूस के बीच विवाद ख़त्म होने की बात की तो तेल की क़ीमत में मज़बूती आई.

समझौते के अनुसार हर दिन लगभग एक करोड़ बैरल की कटौती

इस समझौते के अनुसार 01 मई 2020 से ओपेक प्लस देश तेल उत्पादन में हर दिन लगभग एक करोड़ बैरल की कटौती करेंगे. इसके साथ ही ओपेक प्लस समूह से अलग अमरीका, कनाडा, ब्राज़ील और नॉर्वे 50 लाख बैरल की कटौती करेंगे.

इसी साल जुलाई से दिसंबर के बीच कटौती को कम कर हर दिन 80 लाख बैरल किया जाएगा. इसके बाद जनवरी 2021 से अप्रैल 2022 तक 60 लाख बैरल तक लाया जाएगा.

भारत की आर्थिक वृद्धि 2020-21 में 1.9 प्रतिशत रहने का अनुमान: आईएमएफ

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 14 अप्रैल 2020 को वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर सिर्फ 1.9 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है. हालांकि, आईएमएफ ने कहा कि इसके बावजूद भारत दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था का तमगा अपने पास बरकरार रखेगा. वहीं, आईएमएफ ने इस दौरान चीन की वृद्धि दर 1.2 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है.

आईएमएफ ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी और उसके कारण विश्व भर में आर्थिक गतिविधियां ठप होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था भीषण मंदी की ओर बढ़ रही है. यह साल 1930 में आयी महामंदी के बाद सबसे बड़ी मंदी है. भारत में आर्थिक वृद्धि का यह स्तर रहता है तो यह साल 1991 में शुरू उदारीकरण के बाद सबसे कम वृद्धि दर होगी.

तीव्र वृद्धि से उभरती अर्थव्यवस्था

मुद्राकोष ने इसके बावजूद विश्व अर्थव्यवस्था के बारे में अपनी रिपोर्ट के नये संस्करण में भारत को तीव्र वृद्धि वाली उभरती अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में रखा है. भारत उन दो बड़े देशों में शामिल है जहां 2020 में वृद्धि दर सकारात्मक होगी. दूसरा देश चीन है जहां आईएमएफ के मुताबिक 1.2 प्रतिशत वृद्धि दर रह सकती है.

आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने क्या कहा?

आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा कि हमारा अनुमान है कि साल 2020 में वैश्विक वृद्धि में 3 प्रतिशत की गिरावट आएगी. यह जनवरी 2020 से 6.3 प्रतिशत की गिरावट है. इतने कम समय में बड़ा बदलाव किया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी से सभी क्षेत्रों में वृद्धि दर प्रभावित होगी. गोपीनाथ ने कहा कि यह संकट गहरा है और इसके लोगों के जीवन तथा आजीविका पर प्रभाव को लेकर काफी अनिश्चितता है.

दुनिया की महामंदी

उल्लेखनीय है कि दुनिया की महामंदी साल 1929 में अमेरिका में शुरु हुई. उस समय न्यूयार्क शेयर बाजार में बड़ी गिरावट के साथ निवेशकों को लाखों डॉलर की चपत के बाद इसकी शुरुआत हुई थी.

आर्थिक वृद्धि में गिरावट

आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक विकसित देशों की श्रेणी में ज्यादातर देशों की आर्थिक वृद्धि में गिरावट आएगी. इसमें अमेरिका (5.9 प्रतिशत की गिरावट), जापान (5.2 प्रतिशत की गिरावट), ब्रिटेन (6.5 प्रतिशत की गिरावट), जर्मनी (7.0 प्रतिशत की गिरावट), फ्रांस (7.2 प्रतिशत की गिरावट), इटली (9.1 प्रतिशत की गिरावट) और स्पेन 8.0 प्रतिशत की गिरावट में रह सकता है.

चीन में राजकोषीय में सुधार

रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में अच्छी-खासी राजकोषीय सहायता के साथ साल 2020 की शेष अवधि में सुधार आएगा और वृद्धि दर 1.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है. क्षेत्र की कई अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि दर हल्की होने का अनुमान है. इसमें भारत (1.9 प्रतिशत) और इंडोनेशिया (0.5 प्रतिशत) शामिल हैं. वहीं थाईलैंड में 6.7 प्रतिशत की गिरावट के साथ कुछ अन्य देशों में आर्थिक वृद्धि में गिरावट की अनुमान व्यक्त की गयी है.

आर्थिक वृद्धि में बड़ी गिरावट

मुद्राकोष के मुताबिक दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी आर्थिक वृद्धि में बड़ी गिरावट का अनुमान है. इसमें लातिन अमेरिका (5.2 प्रतिशत की गिरावट) शामिल हैं.

ब्राजील में आर्थिक वृद्धि दर में 5.3 प्रतिशत और मेक्सिको में 6.6 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है.

उभरते और विकासशील यूरोप में वृद्धि दर में 5.2 प्रतिशत की गिरावट जबकि रूस की अर्थव्यवस्था में 5.5 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है.

रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में वृद्धि दर में 2.8 प्रतिशत की गिरावट आने की आशंका हैं. इसमें सऊदी अरब की जीडीपी वृद्धि 2.3 प्रतिशत सिकुड़ सकती है.

2021 में आर्थिक वृद्धि दर

रिपोर्ट में भारत के बारे में कहा गया है कि साल 2021 में आर्थिक वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत जबकि चीन की 9.2 प्रतिशत रहेगी. वहीं अमेरिका और जापान की जीडीपी वृद्धि दर क्रमश: 4.5 प्रतिशत और 3.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना: 32 करोड़ भारतीयों को मिली करोड़ों रुपये की आर्थिक मदद

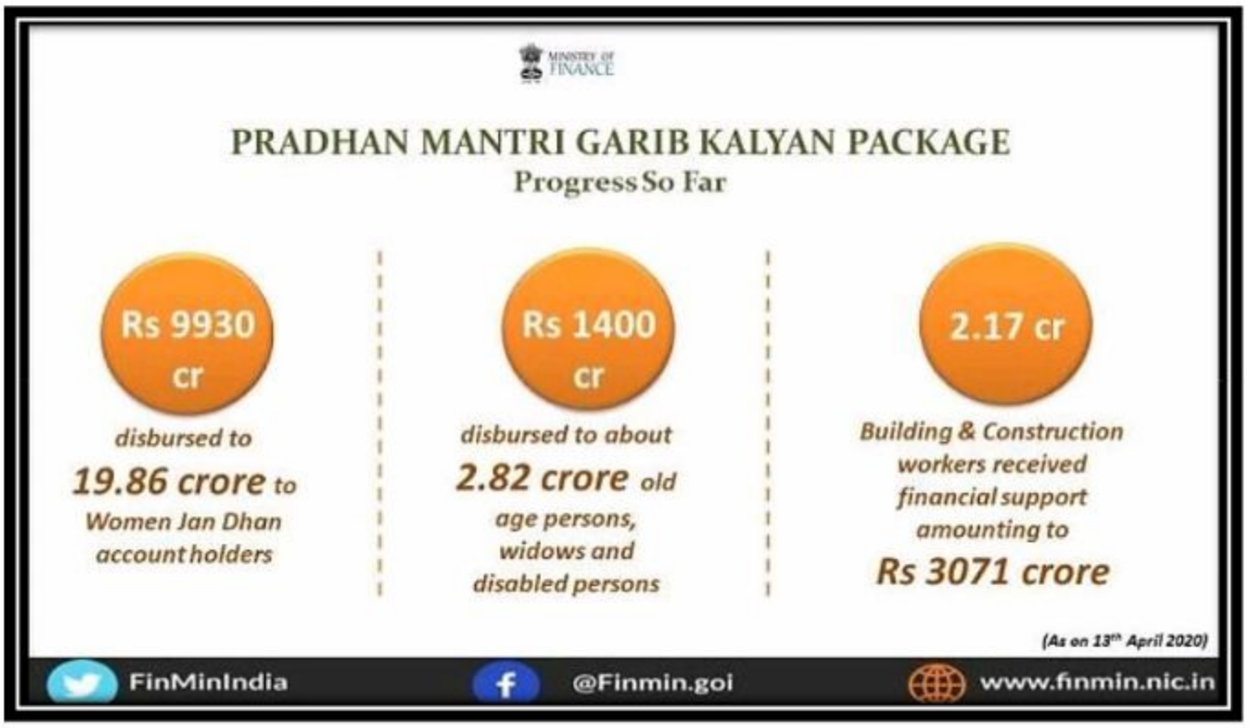

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKP) के तहत 13 अप्रैल 2020 तक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना से लगभग 32 करोड़ गरीब और कमजोर लोगों को लाभ हुआ है.

यह जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 13 अप्रैल, 2020 को साझा की थी. कोविड - 19 प्रकोप के कारण लागू किये गए लॉकडाउन से बचने में मदद करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के तहत, लगभग 29,352 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को लगभग 32 करोड़ लोगों के खातों में सीधे जमा करवाया गया था.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 26 मार्च, 2020 को 1.70 लाख करोड़ रुपये की प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKP) की घोषणा की गई थी ताकि लॉकडाउन के दुष्प्रभावों से समाज के कमजोर वर्ग को सुरक्षा प्रदान की जा सके.

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना: हासिल किये गए लक्ष्य

- 32 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को 29,352 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मिली.
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5.29 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न मिलता है.
- उज्ज्वला योजना के तहत 97.8 लाख मुफ्त उज्ज्वला सिलेंडर दिए गए.
- 2.1 लाख EPFO सदस्यों के EPFO खाते से गैर-वापसी योग्य अग्रिम राशि की ऑनलाइन अदायगी की गई जिसकी कुल राशि 510 करोड़ रुपये थी.
- PM-KISAN की पहली किश्त: 14,946 करोड़ रुपये 7.47 करोड़ किसानों के खातों में जमा करवाये गये.
- 19.86 करोड़ महिला जन धन खाता धारकों के खातों में 9930 करोड़ रुपये जमा करवाये गए हैं.
- लगभग 2.82 करोड़ बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग जनों के बीच 1400 करोड़ रुपये की सहायता राशि का वितरण किया गया है.
- 2.17 करोड़ भवन एवं निर्माण श्रमिकों को 3071 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, भारत सरकार ने महिलाओं, गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को मुफ्त अनाज और नकद भुगतान की भी घोषणा की थी.

इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी केंद्र और राज्य सरकारें, वित्त मंत्रालय और अन्य सभी संबंधित मंत्रालय और अधिकारी कर रहे हैं.

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना: विस्तृत विवरण

डिजिटल तकनीक

लाभार्थियों के खातों में धनराशि का तीव्र और कुशल हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार डिजिटल तकनीक जैसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का उपयोग कर रही है.

यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण क्या है?

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तहत, राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जमा की जाती है. इससे न केवल दक्षता में सुधार होता है, बल्कि यह अधिक विश्वसनीय भी है.

14 अप्रैल 2020 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कुल प्रत्यक्ष लाभ अंतरण:

योजना	लाभार्थियों की संख्या	राशि (रुपये)
PMJDY महिला खाता धारकों को सहायता	19.86 करोड़ (97%)	9930 करोड़
NSAP को सहायता (बुजुर्ग विधवायें, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक)	2.82 करोड़ (100%)	1405 करोड़
PM-KISAN योजना के तहत किसानों को अग्रिम भुगतान	7.47 करोड़ (8 करोड़ में से)	14,946 करोड़
भवन एवं अन्य विनिर्माण श्रमिकों को सहायता	2.17 करोड़	3071 करोड़
कुल योग	32.32 करोड़	29,352 करोड़

विभिन्न योजनाओं के तहत प्रगति:

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना: अब तक, 31 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने अप्रैल माह के लिए 40 लाख मीट्रिक टन में से 20.11 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न लिया है. 16 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 5.29 करोड़ लाभार्थियों को 1.19 करोड़ राशन कार्डों द्वारा इस अन्न भंडार में से लगभग 2.65 लाख मीट्रिक टन मुफ्त राशन वितरित किया गया है. इसके अलावा, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3985 मीट्रिक टन दलहन भी भेजा गया है.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: इस योजना के तहत अब तक लगभग 1.39 करोड़ सिलेंडर बुक किए जा चुके हैं और लगभग 97.8 लाख मुफ्त सिलेंडर पहले ही लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं.

EPFO खाता धारक: लगभग 2.1 लाख EPFOसदस्यों को कुल 510 करोड़ रुपये की ऑनलाइन गैर-वापसी योग्य अग्रिम राशि का लाभ दिया गया है.

3 महीने के लिए EPF योगदान: 100 श्रमिकों वाली सभी कंपनियों में प्रति माह 15000 रुपये से कम वेतन लेने वाले EPFO के सदस्यों को सहायता के तौर पर उनकी वेत्तन राशि का 24 प्रतिशत प्रदान किया जायेगा. वहीं, अप्रैल महीने के लिए 1000 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है. इस योजना से लगभग 78.74 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है.

मनरेगा: मनरेगा की दर में वृद्धि की गई है और इस संबंध में अधिसूचना 1 अप्रैल, 2020 को जारी की गई थी. देश के विभिन्न राज्यों को मजदूरी/ वेतन और सामग्री दोनों के लंबित बकाये का भुगतान करने के लिए 7100 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.

बीमा योजना: न्यू इंडिया एश्योरेंस द्वारा एक नई बीमा योजना शुरु की गई है जिसके तहत सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में कार्यरत लगभग 22.12 लाख स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है.

किसान समर्थन: लगभग 7.47 किसानों को लाभान्वित करते हुए 14,946 करोड़ रुपये की PM-KISAN की पहली किस्त का वितरण किया गया. लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में 2000 रु. प्रदान किये गए हैं.

जन धन योजना: PMJDY के तहत, लगभग 19.86 करोड़ महिला जन धन खाता धारकों को उनके खाते में 500 रु. प्रदान किये गए हैं. इस योजना के तहत अब तक कुल 9930 करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है.

बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता: राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत, लगभग 2.82 करोड़ बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को 1,400 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है. इस योजना के तहत, प्रत्येक लाभार्थी को पहली किस्त के रूप में 500 रुपये की राशि प्राप्त हुई है. अगले महीने 500 रुपये की एक अन्य किस्त का भुगतान किया जाएगा.

भवन एवं अन्य विनिर्माण श्रमिकों के लिए सहायता योजना: इस योजना के तहत, राज्य सरकारों द्वारा प्रबंधित भवन और विनिर्माण श्रमिक निधि के तहत लगभग 2.17 करोड़ भवन एवं विनिर्माण श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए 3,071 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई थी.

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की बड़ी घोषणा, रिवर्स रेपो रेट में 0.25 फीसदी कटौती

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 17 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस के चलते संकट से जूझ रही भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जानकारी दी. आरबीआई ने कोरोना संकट के बीच आर्थिक मदद का घोषणा किया है. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बाजार में कैश की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी.

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना के चलते दुनिया को 9 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होने की आशंका है जो कि कई विकसित देशों की अर्थव्यवस्था के बराबर है. हालांकि, उन्होंने कहा कि वैश्विक मंदी के अनुमान के बीच भारत की विकास दर अब भी पॉजिटिव रहने का अनुमान है.

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की मुख्य बातें

- नाबार्ड, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक के लिए आरबीआई ने राहत की घोषणा की. नाबार्ड, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक को 50000 करोड़ की मदद का घोषणा किया गया.
- आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, देश की आर्थिक वृद्धि दर 1.9 फीसदी रहने का अनुमान है.
- आरबीआई कोरोना वायरस को लेकर बहुत ही सतर्क है. रिजर्व बैंक इसकी करीब से निगरानी कर रहा है. 2020 वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी मंदी का साल है.
- आरबीआई गवर्नर ने कहा कि देश में बैंकिंग कारोबार सामान्य बनाए रखने की कोशिश जारी है. वित्तीय संस्थानों ने विशेष तैयारी की है. देश में 91 फीसदी एटीएम काम कर रहे हैं.
- रिवर्स रेपो रेट 0.25 फीसदी से घटाकर 3.75 फीसदी कर दी गई. टीएलटीआरओ के जरिए आरबीआई सिस्टम में 50,000 करोड़ रुपये डालेगा.

रिवर्स रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिवर्स रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती का घोषणा किया, इसी के साथ बाजार में नकदी संकट ना आए इसके लिए भी 50 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त मदद की बात कही. आरबीआई की ओर से रिवर्स रेपो रेट में कमी करने से सीधी मदद आम लोगों को पहुंच सकती है, इस घोषणा से बैंकों के पास ज्यादा पैसा उपलब्ध होगा. ऐसे में बैंक आम आदमी को कर्ज दे सकेंगे. ऐसे में इस घोषणा के बाद बैंकों पर कर्ज पर ब्याज दर कम करने का दबाव होगा.

दुनिया में सबसे बड़ी मंदी

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इस समय 150 से अधिक अधिकारी लगातार क्वारनटीन होकर भी काम कर रहे हैं और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं.

शक्तिकांत दास ने कहा कि आईएमएफ ने इस बात का अनुमान लगाया है कि दुनिया में सबसे बड़ी मंदी आने वाली है, जो कि खतरे की घंटी है. कई देशों में आयात और निर्यात में भारी गिरावट देखने को मिली है.

जी-20 देशों में भारत की स्थिति सबसे अच्छा

कोरोना संकट की वजह से भारत की जीडीपी 1.9 फीसदी की रफ्तार से बढ़ेगी, G20 देशों में ये सबसे अच्छा स्थिति है. दुनिया में 9 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होने का अनुमान है. लेकिन जब कोरोना का दौर चला जाएगा तो भारत की जीडीपी एक बार फिर 7 फीसदी से अधिक की रफ्तार से बढ़ेगी. आरबीआई गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मार्च 2020 में निर्यात में भारी गिरावट आई है, इसके बावजूद विदेशी मुद्रा भंडार 476 अरब डॉलर का है जो 11 महीने के आयात के लिए काफी है.

27 मार्च को भी किए थे घोषणा

आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इससे पहले 27 मार्च को घोषणा किया था कि रेपो रेट में 0.75 फीसदी की कटौती की गई है और ये 5.15 फीसदी से घटाकर 4.40 फीसदी कर दी गई है. साथ ही आरबीआई गवर्नर ने बैंकों को सलाह दी थी कि वे अगले तीन महीने तक ग्राहकों को ईएमआई में राहत दें.

वित्त मंत्री दूसरी जी 20 वित्त मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल हुई

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 अप्रैल को दूसरी जी 20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के आभासी सत्र में भाग लिया. इस आभासी बैठक (वर्चुअल मीटिंग) का उद्देश्य इस कोविड -19 महामारी संकट के दौरान वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण पर चर्चा करना था. यह बैठक सऊदी अरब की अध्यक्षता में हुई. वित्त मंत्री ने इस सत्र के दौरान कोविड -19 के लिए उपयुक्त प्रतिक्रिया के तौर पर जी 20 एक्शन प्लान की तैयारी में सऊदी अरब की अध्यक्षता में किये गए प्रयासों की सराहना की.

निर्मला सीतारमण ने 31 मार्च, 2020 को जी 20 एफ़एमसीबीजी की दूसरी विशेष आभासी बैठक मेंभी भारत का प्रतिनिधित्व किया था. गत 31 मार्च को हुई इस बैठक में, उन्होंने समन्वित कार्रवाइयों के

महत्व के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में भी बात की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में यह वित्तीय प्रणाली मदद कर रही है.

जी 20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दूसरी बैठक की मुख्य विशेषताएं

- इस सत्र में, निर्मला सीतारमण ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के साथ-साथ लोगों के जीवन और आजीविका की सुरक्षा के लिए वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला.
- वित्त मंत्री ने संकट के समय कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहलों के बारे में भी इस बैठक में जानकारी साझा की.
- वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की इस बैठक में हमारी वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा योजनाबद्ध आर्थिक सुधारों के लिए किये गये प्रयासों में वित्तीय समावेशन जैसे उपाय भी शामिल थे.
- केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस बैठक के दौरान जी 20 की प्रतिक्रिया संबंधी एक्शन प्लान (कार्य योजना) की भी सराहना की और इसे सही दिशा में एक कदम बताया जो कोविड -19 महामारी के खिलाफ व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों का मार्गदर्शन करेगा.

  कोविड -19 के खिलाफ भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय:
- भारत ने 320 मिलियन से अधिक लोगों को 3.9 बिलियन अमरीकी डालर की वित्तीय सहायता दी है. सार्वजनिक स्थानों में लोगों के आपसी संपर्क को कम करने के लिए डिजिटल तकनीक के माध्यम से यह सहायता दी गई है.
- भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए मौद्रिक उपायों ने बाजार को मुक्त करने में मदद की है और क्रेडिट प्रवाह को सुगम बना दिया है.
- भारत सरकार के मौद्रिक उपायों में 50 बिलियन अमरीकी डालर की नकदी सहायता, ऋण सुगमता के उपाय, सावधि ऋणों की किस्तों पर राहत, पूंजी वित्तपोषण (वित्तीय सहायता) को सरल बनाना और ऐसे वित्तपोषण पर ब्याज भुगतान को कम करना शामिल है.

कोविड -19 महामारी के जवाब में जी 20 की प्रतिक्रिया संबंधी एक्शन प्लान

जी 20 सदस्य देश अपने जी 20 नेताओं के निर्देश पर एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं. इस योजना का उद्देश्य निम्नलिखित है:

• आत्मविश्वास बहाल करना.

• वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना.

• लोगों की जान बचाना.

• लोगों की नौकरियों और आय की सुरक्षा करना.

• विकास को फिर से तीव्र गति से बढ़ाना और इसे मजबूत बनाना.

• सार्वजनिक स्वास्थ्य और वित्तीय उपायों के संबंध में आपस में समन्वय करना.

• ऐसे देशों को सहायता प्रदान करना जिन्हें इस समय सहायता की आवश्यकता है.

• वैश्विक आर्थिक श्रृंखला में अवरोध को कम करना.

---------X----------x----------x------

पर्यावरण

यूक्रेन के चेर्नोबिल के जंगलों में लगी आग, कई गुना बढ़ा विकिरण

यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा स्टेशन के आसपास के क्षेत्र आग लग गई है. यह आग दो अलग-अलग जगहों पर लगी है. यूक्रेनीफायर फाइटर आग पर काबू पाने की कोशिश में लगे हुए हैं. इस साल 4 अप्रैल 2020 को दुनिया के सबसे भीषण परमाणु हादसे की जगह अर्थात चेर्नोबिल के पास प्रतिबंधित क्षेत्र के जंगल में आग भड़कने के बाद यूक्रेनी अधिकारियों ने विकिरण के स्तर में अत्यधिक वृद्धि की सूचना दी है.

यूक्रेन की राज्य पारिस्थितिक निरीक्षण सेवा के प्रमुख, येगोर फिर्सोव ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि अग्निशमन दल आग बुझाने का प्रयास कर रहा है. उन्होंने लिखा कि, "स्थिति बहुत गंभीर है क्योंकि यह आग चेर्नोबिल के 20 हेक्टेयर के दायरे में फैल गई है और कुल मिलाकर 100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में यह आग फ़ैली हुई हैं".

उन्होंने आगे यह भी लिखा है कि, "यह एक बुरी खबर है - विकिरण आग के केंद्र में सामान्य से कहीं अधिक है". फ़िर्सोव ने अपनी पोस्ट में एक वीडियो भी अपलोड किया था जिसमें एक गीगर काउंटर दिखाया गया था जिसमें सामान्य से 16 गुना अधिक विकिरण दिख रहा था.

जंगल में आग कैसे लगी?

येगोर फ़िर्सोव के अनुसार, पहले किसी ने घास को आग लगा दी और फिर आग फ़ैल गई और पेड़ों में लग गई. यूक्रेन ने खेतों या घास को जलाने के लिए 175 UAH का जुर्माना लगाया है लेकिन इसमें अभी भी हर साल ऐसी आग लगने के मामले आते हैं. फ़िर्सोव ने आगजनी के दंड को कम से कम 50 से 100 बार बढ़ाने की सिफारिश की है.

यूक्रेन इस स्थिति से कैसे निपट रहा है?

यूक्रेन ने आग से निपटने के लिए दो विमानों, एक हेलीकॉप्टर और लगभग 100 अग्निशामकों को तैनात किया. लेकिन 5 अप्रैल की सुबह तक आग दिखाई नहीं दे रही थी और विकिरण में कोई वृद्धि नहीं देखी गई थी. हालांकि, आपातकालीन सेवा की रिपोर्ट के मुताबिक, 4 अप्रैल को कुछ क्षेत्रों में विकिरण के स्तर में वृद्धि से इस आग को बुझाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. आपातकालीन सेवा की इस रिपोर्ट में यह जोर देकर कहा गया कि, आसपास के शहरों में रहने वाले लोगों के लिए इस आग से कोई खतरा नहीं था.

चेर्नोबिल आपदा क्या है?

चेर्नोबिल आपदा दुनिया की सबसे ख़तरनाक परमाणु दुर्घटना है. यह दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के प्रिपयात शहर के पास चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में नंबर 4 परमाणु रिएक्टर में घटी थी.

चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना कैसे हुई?

यह दुर्घटना आरबीएमके प्रकार के परमाणु रिएक्टर के सुरक्षा परीक्षण के दौरान हुई. परीक्षण के दौरान इस परमाणु रिएक्टर की शक्ति अप्रत्याशित रूप से शून्य तक कम हो गई और ऑपरेटर केवल निर्दिष्ट परीक्षण शक्ति को बहाल करने में सक्षम थे, जिस कारण यह रिएक्टर अस्थिर हो गया.

यद्यपि परिचालन निर्देशों में जोखिम का उल्लेख था, फिर भी ऑपरेटर्स विद्युत परीक्षण करते रहे और परीक्षण पूरा होने के बाद, उन्होंने रिएक्टर को बंद करना शुरु कर दिया. लेकिन रिएक्टर में डिजाइन की खामियों और अस्थिर परिस्थितियों की वजह से इस रिएक्टर में अनियंत्रित परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया (न्यूक्लियर चेन रिएक्शन) शुरु हो गई.

इससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा पैदा हुई, वाष्पीकरण ने शीतल जल को नष्ट कर दिया और एक अत्यधिक विनाशकारी भाप विस्फोट ने रिएक्टर कोर को तोड़ दिया. इसके बाद एक खुली रिएक्टर कोर आग लग गई, जिससे लगभग नौ दिनों तक तत्कालीन यूएसएसआर और पश्चिमी यूरोप के कुछ हिस्सों में हवा से फ़ैलने वाला रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलता ही रहा. आख़िरकार, इस आग और रेडियोधर्मी प्रदूषण पर 4 मई को काबू पा लिया गया.

विकिरण को रोकने के प्रयास

दुर्घटना होने के 36 घंटे के भीतर 10 किमी का दायरा बहिष्करण क्षेत्र बनाया गया और लगभग 49,000 लोगों को इस दुर्घटना ग्रस्त क्षेत्र से बाहर निकाला गया. बाद में बहिष्करण क्षेत्र को बढ़ाकर 30 किमी कर दिया गया और लगभग 68,000 लोगों को इस क्षेत्र से सुरक्षित स्थान पर भेजा गया.

चेर्नोबिल दुर्घटना में हताहतों की संख्या

इस परमाणु रिएक्टर के विस्फोट में दो ऑपरेटिंग कर्मचारियों की मौत हो गई और ऐसे लगभग 134 स्टेशन स्टाफ और फायरमैन, जो इस आपातकालीन प्रतिक्रिया में शामिल थे, उन्हें आयनीकृत विकिरण की उच्च खुराक देने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया. उनमें से 28 लोगों की आने वाले कुछ दिनों और महीनों में मृत्यु हो गई और अगले 10 वर्षों के भीतर इस दुर्घटना में बचे हुए अन्य लोगों में से 14 लोगों की विकिरण-प्रेरित कैंसर से मौत होने की आशंका जताई गई.

परमाणु विकिरण के प्रभाव की जांच करने वाली संयुक्त राष्ट्र की वैज्ञानिक समिति (UNSCEAR) के अनुसार, दस्तावेजों में विकिरण के संपर्क में ज्यादा आने के कारण वर्तमान में 100 से कम मौतें होने की संभावना दी गई है. हालांकि विकिरण-जोखिम से संबंधित कुल मौतों की संख्या निर्धारित करना मुश्किल है. चेर्नोबिल आपदा के परिणामस्वरूप यूरोप में लगभग 9000-16000 लोगों की मृत्यु होने की जानकारी दी गई.

चेर्नोबिल आपदा का प्रभाव

चेर्नोबिल आपदा को लागत और हताहतों की संख्या के मुताबिक, मानव इतिहास में सबसे ख़तरनाक परमाणु ऊर्जा दुर्घटना माना जाता है. संयंत्र के मलबे से रेडियोधर्मी प्रदूषण के आगे प्रसार को कम करने के लिए दिसंबर 1986 तक एक सुरक्षात्मक चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के चारों तरफ़ पत्थर की मजबूत दीवार (कास्केट) बनाई गई. इसने इस साइट पर ऐसे अन्य क्षति रहित रिएक्टरों के कर्मचारियों की भी रक्षा की, जो रिएक्टर लगातार काम करते रहे.

हालांकि, इस कास्केट के क्षतिग्रस्त होने के कारण, इस क्षेत्र को वर्ष 2017 में घेराबंदी कर दी गई और रिएक्टर के अवशेष और कास्केट को हटाने के लिए परमाणु शोधन का आदेश दिया गया. यह परमाणु शोधन वर्ष 2065 तक पूरा होगा.

वर्तमान परिवेश

वर्तमान में, लोगों को चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा स्टेशन के 30 किमी के भीतर रहने की अनुमति नहीं है. शेष तीन रिएक्टर वर्ष 2000 तक बिजली पैदा करते रहे, उसके बाद यह पावर स्टेशन बंद कर दिया गया. हाल ही की जंगल की आग 2,600 वर्ग किमी के उस चेरनोबिल अपवर्जन क्षेत्र के भीतर लगी थी जिसे 1986 की आपदा के बाद बनाया गया था. यह क्षेत्र ऐसे 200 लोगों को छोड़कर काफी हद तक खाली है, जो वह क्षेत्र छोड़कर नहीं गये. आपदा के 34 साल बाद भी इस क्षेत्र में विकिरण का स्तर सामान्य नहीं हुआ है.

बढ़ते तापमान की वजह से ग्रेट बैरियर रीफ को सबसे ज्यादा नुकसान

ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ़ में समुद्र के लगातार बढ़ते हुए तापमान के कारण काफी हानिकारक कोरल ब्लीचिंग हो रही है. गत 07 अप्रैल 2020 को वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया के सबसे विशाल जीवित प्राणी को होने वाले खतरे के बारे में बताया.

जेम्स कुक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टेरी ह्यूजेस ने उस व्यापक सर्वेक्षण के बारे में जानकारी दी है जिसमें यह बताया गया है कि बढ़ते तापमान के कारण केवल पिछले 5 वर्षों में 2300 किमी रीफ़ सिस्टम में तीसरी विशाल ब्लीचिंग हुई है. पहली बार इस रीफ़ ब्लीचिंग के बारे में वर्ष 1998 में पता चला था. रिकॉर्ड के मुताबिक यह सबसे गर्म वर्ष था. तापमान में निरंतर वृद्धि के कारण कोरल ब्लीचिंग में लगातार वृद्धि हुई जिस वजह से कोरल को ठीक होने में कम समय मिला.

कोरल ब्लीचिंग के कारण:

कोरल ब्लीचिंग तब होती है जब समुद्र के तापमान में बदलाव के कारण स्वस्थ कोरल तनावग्रस्त हो जाते हैं. इस कारण कोरल अपने एल्गी (शैवाल) निष्कासित करते हैं और यही एल्गी उनके टिश्यूज़ (ऊतकों) में रहते हैं और इन एल्गीज़ के न रहने पर कोरल्स का चमकदार रंग रंगहीन हो जाता है.

ग्रेट बैरियर रीफ़ कोरल ब्लीचिंग: मुख्य विशेषताएं

- ग्रेट बैरियर रीफ़ के सभी तीनों क्षेत्र - मध्य, उत्तरी और अब दक्षिणी क्षेत्र के काफी बड़े हिस्से बढ़ते तापमान के कारण अत्यधिक प्रवाल विरंजन (कोरल ब्लीचिंग) से प्रभावित हुए हैं.
- फरवरी माह में सबसे अधिक समुद्री तापमान होने के कारण ग्रेट बैरियर रीफ़ को नुकसान हुआ.
- ऑस्ट्रेलिया की पर्यटन अर्थव्यवस्था में ग्रेट बैरियर रीफ़ का योगदान अनुमानतः 4 बिलियन डॉलर प्रति होता है. लेकिन अब ग्रेट बैरियर रीफ़ अपना विश्व विरासत का दर्जा खो सकता है.

ग्रेट बैरियर रीफ़ के बारे में:

ग्रेट बैरियर रीफ़ दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ़ सिस्टम है जो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के तट पर कोरल सागर में स्थित है.
सबसे बड़ा कोरल रीफ़ सिस्टम 2900 से अधिक अलग किस्म की कोरल रीफ़्स से बना है. ग्रेट बैरियर रीफ़ दुनिया की सबसे बड़ी एकल संरचना है जो जीवित प्राणियों से मिलकर बनी है. यह संरचना कोरल पॉलीप्स के तौर पर प्रसिद्ध अरबों छोटे जीवों के एक साथ मिलने से बनी है.

रीफ़ से हमें पृथ्वी पर जीवन की विशाल विविधता का पता चलता है. इसे वर्ष 1980 में विश्व विरासत स्थल के रूप में चुना गया था. यह रीफ़ दुनिया के सात अजूबों में से एक है.

--------X----------X----------X----------